नीलू प्रिंटिंग प्रेस
हर प्रकार की वेब ऑफसेट एवं रंगीन व बहुरंगीन प्रिंटिंग के लिए नोएडा में एक मात्र स्थान
ई 33, सेक्टर 7 नोएडा (यूपी)
फोन नं. : 9811157562

फरीदाबाद हरियाणा का नंबर 1 समाचार पत्र
भेदी नज़र
संस्थापक : स्वाधीनता सेनानी सुखवासी लाल शर्मा (ब्रह्मलीन)
ई- पेपर पढ़ने के लिए लॉगऑन करें- www.bhedinazar.com
दिल्ली, रविवार 12 जुलाई 2026
दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश को प्रमुख हिन्दी दैनिक

आवश्यकता है
1- न्यूज एडीटर
2- एकाउन्टेंट
3- मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव (फार एडवर्टाइजमेंट)
4- चपरासी
सम्पर्क करें- 9811157562
समय: 3:00 से 5:00 PM

वर्ष : 23 अंक : 90 | Email : bhedinazardaily@gmail.com | RNI NO. DEL/HIN/2004/13528 | Postal REG. No. HR (FBD) -260/2023/25 | पृष्ठ : 12 मूल्य : 1 रुपये

आईएनएस महेंद्रगिरि नौसेना में शामिल

समंदर का सिकंदर

स्वदेशी मिसाइल-सेंसर से लैस,75 फीसदी से ज्यादा हिस्सा भारत में बना
मॉडर्न हथियारों से लैस,राजनाथ बोले-आंध्र प्रदेश बनेगा देश का ड्रोन हब

विशाखापत्तनम (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस महेंद्रगिरि को भारतीय नौसेना में शामिल (कमीशन) किया। महेंद्रगिरि प्रोजेक्ट-17ए की नीलगिरि कैटेगरी का छठा स्टेल्थ फ्रिगेट (युद्धपोत) है।

इसे बनाने में 75 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस महेंद्रगिरि स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। यह हवाई हमलों, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। यह हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में आठ ड्रोन कंपनियों के समूह के साथ ड्रोन सिटी विकसित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह सूरत डायमंड सिटी और बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में कुरनूल देश का ड्रोन हब बनेगा।

पर्वतों-नदियों के नाम पर युद्धपोतों के नाम रखे

आईएनएस महेंद्रगिरि का नाम जिस महेंद्रगिरि पर्वत पर रखा गया है, उसका धार्मिक महत्व भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत भगवान परशुराम की तपस्थली थी। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय नौसेना अपनी कई युद्धपोतों के नाम देश के ऐतिहासिक पर्वतों, नदियों के नाम रखे हैं।

75 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी तकनीक

इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। युद्धपोत में 75 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण में देशभर की कई कंपनियों ने भी योगदान दिया है, जिससे रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। महेंद्रगिरि में आधुनिक सरफेस-टू-सरफेस और सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। महेंद्रगिरि में उन्नत स्टेल्थ तकनीक दी गई है, जिससे इसकी रडार पर पहचान करना मुश्किल होगा।

बारुईपुर हिंसा में मारे गए इंद्रजीत के परिजनों को मिलेंगे 25 लाख

- भाई को नौकरी भी देगी सरकार,सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान

कोलकाता (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शनिवार को दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में दुष्कर्म व हत्या की शिकार नाबालिग के परिवार के साथ भीड़ की पिटाई में मारे गए इंद्रजीत मंडल के स्वजन से मुलाकात की। इंद्रजीत के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। उनके बड़े भाई को सूर्यपुर पुलिस चौकी में सिविक वालंटियर की नौकरी भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ भी पूरी तरह खड़ी है। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने सूर्यपुर में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि नाबालिग के स्वजन ने चार दिन पहले पुलिस चौकी की मांग की थी, जिसे रिकार्ड समय में पूरा किया गया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री इंद्रजीत मंडल के घर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि 35 वर्षीय युवक की पहचान देखकर उसकी हत्या की गई। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि चुनाव में हार के बाद कुछ राजनीतिक तत्वों, अतिवाम संगठनों और कट्टरपंथी समूहों ने माहौल भड़काने में भूमिका निभाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वीडियो फुटेज में पहचान हुई है, उन सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंद्रजीत के परिवार की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। उनके घर की मरम्मत कराई गई है।

DEV MEDICARE CHEMIST
Your Trusted Medical Store
SECTOR 7, FARIDABAD
Allopaathic & Ayurvedic Medicine
BP & sugar Mechines, Thermometers, Oximeters
DISCOUNT ON VARIOUS MEDICINES
Surgical Items, Baby Products, Health Supplements
Wide Range of Cosmetics
ORDER NOW - 9650518651 (Call/Whatsapp)
Hours: 8 AM to 10 PM
100% Genuine Medicines
Experienced Staff

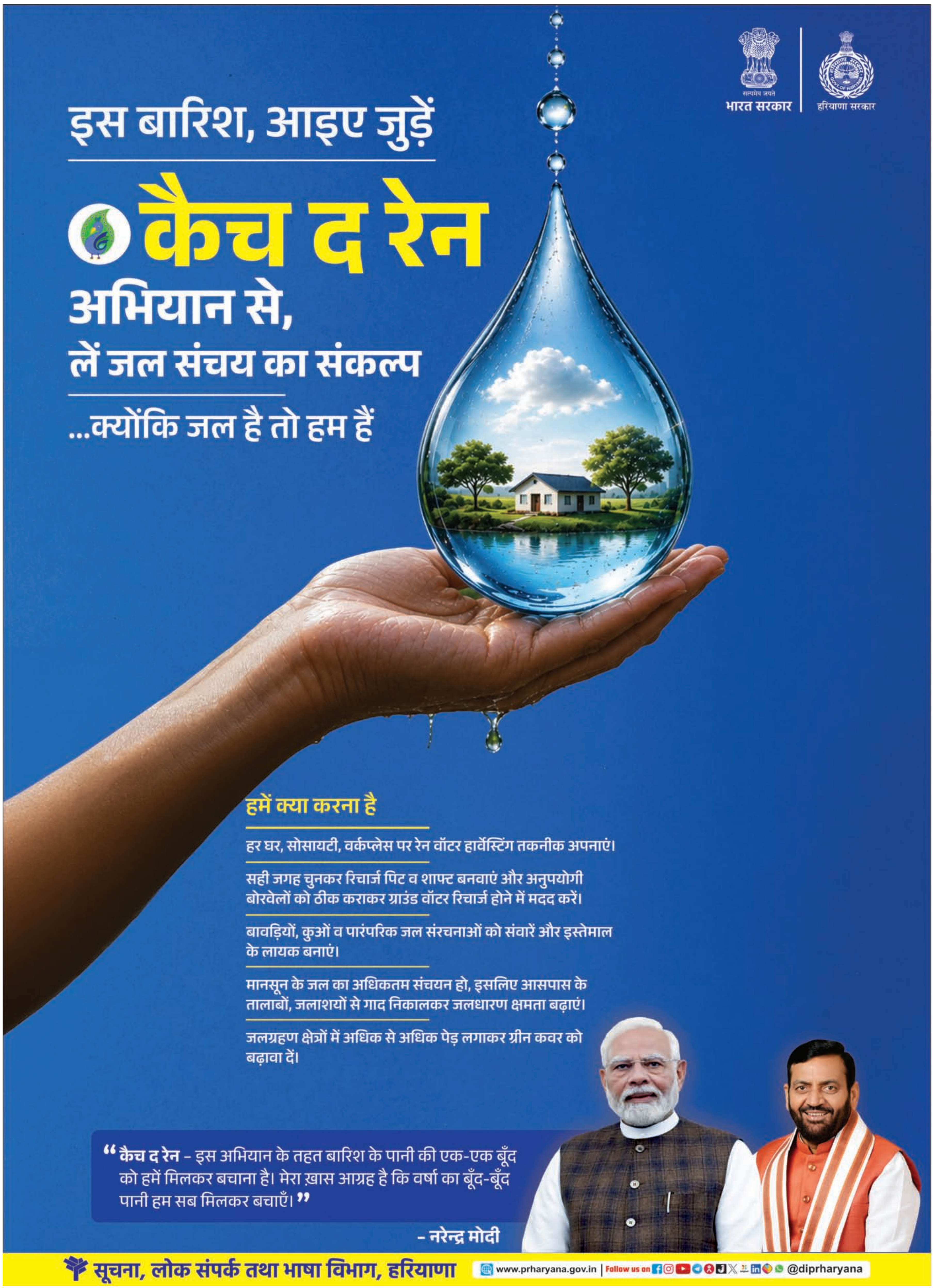

SINCE 2007
TARUN JEWELLERS
TODAY BIS HALLMARK
92% Gold Rate
₹1,36,600/-
Making Charges 8%
100% BUY BACK + EXCHANGE
पिछले 19 वर्षों से हमारी दुकान एक ही स्थान पर हैं।
इसके अलावा हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं हैं।
Shop No. 25, Sec-7, Huda Mkt, FBD
0129-3668332, 9990032657

पंजाब में मात्र 16 दिनों में एस.आई.आर. के तहत 1 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण: अनिंदिता मित्रा

- बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओ.) के निरंतर प्रयासों से हासिल हुई यह अभूतपूर्व उपलब्धि : मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा
- मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतदाताओं से 11–12 जुलाई के विशेष शिविरों में भाग लेने की अपील की ; पंजाब में 'एस.आई.आर. 2026' का घर–घर गणना चरण अंतिम दौर की ओर अग्रसर

चंडीगढ़, भेदी नजर। पंजाब भर में घर-घर जाकर गणना करने की विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) प्रक्रिया निरंतर तेज़ी से जारी है। 25 जून, 2026 को इसकी शुरुआत के मात्र 16 दिनों के भीतर राज्य में 1 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी घरों में 99.34 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण पहले ही पूरा किया जा चुका है, जो यह दर्शाता है कि पूरे प्रदेश के मतदाताओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची तैयार रखने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए गणना प्रपत्रों का संग्रहण और उनका डिजिटलीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओ.), पर्यवेक्षकों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ए.ई.आर.ओ.) तथा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ई.आर.ओ.) के निरंतर प्रयासों की विशेष सराहना की, जिनके सहयोग से राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तथा 24,453 मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्रों का समयबद्ध वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान को और गति देने तथा जनसहभागिता को अधिकतम बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 एवं 12 जुलाई, 2026 को पंजाब के सभी मतदान केंद्रों पर प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के दौरान शेष गणना प्रपत्र भरे जाएंगे, एकत्र किए जाएंगे और उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। साथ ही मतदाता सूची की त्रुटियों एवं लिंकिंग संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाएगा तथा नागरिकों को अपने मतदाता विवरणों के सत्यापन एवं अद्यतन कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 24,453 बी.एल.ओ. 25 जून से 24 जुलाई, 2026 के दौरान पूरे पंजाब में 2,14,61,043 मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) 24 जुलाई, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 3 अगस्त, 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे एवं आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर, 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी, जबकि उनका निपटारा 3 अगस्त से 28 सितंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इन विशेष शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके मतदाता संबंधी सभी विवरण पूर्ण, सही एवं अद्यतन हों, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

मानसून के दौरान बढ़ती बीमारियों के बीच मुख्यमंत्री सेहत योजना पूरे पंजाब में समय पर कैशलेस इलाज सुनिश्चित कर रही है

पंजाब सरकार बुखार, डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों के इलाज का पूरा खर्च उठा रही है; मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मुफ्त उपचार उपलब्ध

चंडीगढ़, भेदी नजर। मानसून की पहली बारिश जहां गर्मी से राहत देती है, वहीं यह स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से भरे मौसम की शुरुआत भी होती है। हर वर्ष पूरे भारत में डेंगू, मलेरिया और बुखार से जुड़ी अन्य बीमारियों के मामलों में वृद्धि दर्ज की जाती है। इस वर्ष भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। अमृतसर की 32 वर्षीय लाभार्थी बलविंदर कौर ने बताया, 'मैंने हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8,400 रुपये का कैशलेस इलाज कराया है।' उन्होंने बताया कि तेज बुखार होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका मुख्यमंत्री सेहत योजना में पंजीकरण कराया। उन्होंने कहा, 'मैं सिलाई का काम करके अपना परिवार चलाती हूं। इस योजना ने समय पर इलाज और आर्थिक सहायता देकर मेरा बोझ कम किया, जिससे मैं अपनी सेहत पर ध्यान दे सकी। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई इस योजना की आभारी हूं, क्योंकि यह जरूरत के समय परिवारों का सच्चा सहारा बनती है।'

वर्ष 2025 में किए गए एक भारतीय अस्पताल अध्ययन में पाया गया कि मानसून के दौरान भर्ती मरीजों में एक्यूट फेब्राइल इलनेस (तीव्र बुखार संबंधी बीमारी) का सबसे सामान्य कारण डेंगू था। यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि समय पर जांच और तत्काल उपचार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानसून से जुड़ी अनेक बीमारियों के शुरुआती लक्षण एक जैसे होते हैं। डॉक्टर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे लगातार बने रहने वाले बुखार को नजरअंदाज न करें। वहीं, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना पात्र परिवारों को अस्पताल के खर्च की चिंता किए बिना कैशलेस इलाज उपलब्ध करा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने मच्छरों और जलजनित मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारियों तथा जांच सुविधाओं को और मजबूत किया है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास पानी जमा न होने देने तथा बुखार के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की।

गैंगस्टरों ते वार का 172वां दिन: पंजाब पुलिस ने 661 स्थानों पर छापेमारी कर 417 लोगों को किया काबू

पुलिस टीमों ने 348 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की

चंडीगढ़, एजेंसी। राज्य में चल रहे 'गैंगस्टरों ते वार' अभियान के 172वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 661 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि 'गैंगस्टरों ते वार' अभियान–पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने की निर्णायक मुहिम–20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 172वें दिन पुलिस टीमों ने 417 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 46,774 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 348 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 13 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर वांछित अपराधियों एवं गैंगस्टरों के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं। इस दौरान पंजाब पुलिस ने नशों के विरुद्ध चलाए जा रहे 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के 497वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 126 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 987 ग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 1,477 नशीली गोलियां तथा 3,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, पिछले 497 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 73,302 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 10 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने एवं पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया।

विद्यार्थियों की मेहनत और प्रतिभा ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव- कृष्ण लाल पंवार

चंडीगढ़, हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि शिक्षा ही वह सबसे सशक्त माध्यम है, जो किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान केवल उनकी उपलब्धियों का अभिनंदन नहीं, बल्कि पूरे समाज में उत्कृष्टता और कड़ी मेहनत की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है।

श्री कृष्ण लाल पंवार शुक्रवार को पानीपत स्थित सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025-26 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी एवं टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यालय के नवीन पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन किया तथा पुस्तकालय का अवलोकन करते हुए विद्यालय की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा भी की। उन्होंने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी एवं टॉपर विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र, स्मृति-चिह्न एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विद्यार्थियों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से उच्च लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने तथा अपने ज्ञान एवं प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं संस्कारयुक्त वातावरण प्रदान करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधक फादर कार्तिक एबल के आशीर्वाद से यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और स्कूल प्रधानाचार्या सिस्टर दीपा सेबास्टियन के मार्गदर्शन में विद्यालय शिक्षा और संस्कारों का केंद्र बन गया है। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विद्यालय की लाइब्रेरी में बच्चों की पुस्तकों हेतु 5 लाख रुपये अनुदान की घोषणा की और कहा कि विद्यालय के ऑडिटोरियम को पूर्ण रूप से वातानुकूलित भी कराया जाएगा।

40 वर्ष पुरानी पानी की समस्या के स्थायी समाधान पर कारसिंधु के ग्रामीणों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का जताया आभार

चंडीगढ़, हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी के चंडीगढ़ आवास पर आज जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव कारसिंधु के ग्रामीणों ने मुलाकात कर गांव की 40 वर्ष पुरानी पानी की समस्या का स्थायी समाधान कराने पर उनका आभार व्यक्त किया।

ग्रामीणों ने कहा कि गांव कारसिंधु लंबे समय से सिंचाई जल वितरण से जुड़ी समस्या का सामना कर रहा था, जिससे किसानों और ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा स्वयं इसकी नियमित समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से लंबित इस समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सका।

इस संबंध में गांव कारसिंधु एवं अलीपुरा (तहसील उचाना, जिला जींद) के बरौला माइनर की आरडी 33850/आर (RD 33850/R) के आउटलेट से तरखा माइनर की आरडी 17150/टीएफ (RD 17150/TF) के आउटलेट में 179/179 एकड़ क्षेत्र के चाक (कमांड एरिया) को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

हिसार को जाम मुक्त और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में गठित कमेटी की बैठक आयोजित

चंडीगढ़, हिसार शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में लक्ष्मी बाई चौक से टाऊन पार्क तक के मार्ग को सिक्स लेन बनाने की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। इस मार्ग पर आने वाले सभी विभागों से एनओसी मिलने के उपरांत लोक निर्माण विभाग द्वारा 3008.56 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। अब जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया की जाएगी।

यह जानकारी आज हिसार को जाम मुक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष समिति की पांचवी बैठक में कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने दी।

कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हिसार को आधुनिक, व्यवस्थित और सुगम यातायात वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक से पहले उन सभी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाने चाहिए, जिनके टेंडर हो चुके हैं।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया कि डाबड़ा चौक जंक्शन का टेंडर भी लगा दिया गया है, जो जल्द ही अलॉट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से लघु सचिवालय के आगे राजगढ़ रोड चौक के चारों तरफ स्लीप रोड बनाने का टेंडर भी लगाया गया है। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के सिटी गेट से आगे चौक बनाने व स्लिप रोड बनाने का कार्य भी आगे बढ़ा है तुलसी चौक पर स्लीप रोड को बनाने की बाधाएं भी दूर हो गई हैं। बैठक में अवगत करवाया गया कि सुशीला भवन के समीप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ स्लिप रोड बनाए जाने की दिशा में निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। बस अड्डे के सामने बने फुटओवर ब्रिज को हटाने का टेंडर भी खुल गया है। इस ब्रिज को भी जल्द हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से शहर के बीकानेर चौक से आरंभ होने वाले पुराने पुल के पुनर्निर्माण और रेड स्क्वेयर मार्केट के लिए अंडरपास बनाने के लिए रेलवे की और से एक प्रस्तुति भी बैठक में दी गई, जिसमें आगामी निर्माण कार्यों की योजना बताई गई थी। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने रेलवे को पूरी परियोजना की थ्रीडी प्रेजेंटशन बनाकर लाने की हिदायत थी। उन्हें बताया गया कि बालसमंद

हरियाणा एवं बिहार के बीच शुरू होगी अंतरराज्यीय बस सेवा

हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक शहरों से बिहार के छह प्रमंडलों तक मिलेगी सीधी बस सेवा

चंडीगढ़, । हरियाणा सरकार ने प्रदेश के यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन के लिए शुक्रवार को द्विपक्षीय बस परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते पर हरियाणा सरकार की ओर से परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा सेखर वुनडरु तथा बिहार सरकार की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त श्री आरिफ अहसन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन आयुक्त श्री अतुल द्विवेदी तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्री अतुल कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे।

इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच नियमित बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित, आरामदायक एवं गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

इन शहरों के बीच चलेगी आधुनिक एसी बस सेवा: द्विपक्षीय समझौते के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित अन्य निर्धारित शहरों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के छह प्रमंडलों–पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर–के लिए आधुनिक वातानुकूलित (एसी) बसों का नियमित परिचालन किया जाएगा। बसों का संचालन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होगा, जिससे यात्रियों को विश्वसनीय एवं समयबद्ध परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

निजी परिवहन पर कम होगी निर्भरता: अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा सेखर वुनडरु ने कहा कि बिहार के साथ हुआ यह समझौता अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे यात्रियों को कम किराये पर गुणवत्तापूर्ण एसी बस सेवा उपलब्ध होगी तथा निजी परिवहन पर उनकी निर्भरता भी कम होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य प्रदेश को देश के प्रमुख राज्यों से बेहतर एवं सुव्यवस्थित बस सेवाओं के माध्यम से जोड़ना है, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती यात्रा का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश के प्रमुख औद्योगिक एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में से एक है। गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और अंबाला जैसे शहरों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार तथा अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विद्यार्थी, व्यापारी एवं अन्य यात्री भी नियमित रूप से दोनों राज्यों के बीच आवागमन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बस सेवा केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हरियाणा एवं बिहार के बीच आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक संबंधों को भी नई गति प्रदान करेगी। दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी तथा निवेश एवं पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

जींद में पीएम मोदी की रैली की कमान संभाल रहे राज्यसभा सांसद संजय भाटिया मैदान से व्यवस्थाओं तक खुद कर रहे निगरानी

चंडीगढ़/जींद, । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित जींद दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन तैयारियों की कमान रैली संयोजक एवं राज्यसभा सांसद संजय भाटिया संभाल रहे हैं। संगठनात्मक बैठकों से लेकर रैली स्थल पर मंच, पंडाल, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं का वे स्वयं निरीक्षण कर तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। *शुक्रवार* को संजय भाटिया ने रैली स्थल पर पंडाल निर्माण कार्य का विधिवत नारियल अर्पित कर शुभारंभ किया तथा हथौड़ा चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई।

रैली स्थल पर संजय भाटिया कार्यकर्ताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित करते नजर आए। उन्होंने पंडाल निर्माण, मंच की रूपरेखा, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उनकी सक्रिय कार्यशैली से स्पष्ट है कि भाजपा इस जनसभा को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन की क्षमता और सुचारु प्रबंधन का भी उदाहरण बनाना चाहती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आयोजित तैयारियों की बैठकों में भी संजय भाटिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें रैली संयोजक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनकी नियमित समीक्षा स्वयं संजय भाटिया कर रहे हैं।

शाहजादपुर के राजकीय महिला महाविद्यालय का नाम अब होगा महारानी पद्मावती राजकीय महिला महाविद्यालय- शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

चंडीगढ़, । हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि राज्य सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और हमारे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को सहेजने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत शाहजादपुर स्थित सरकारी महिला महाविद्यालय का नाम बदलकर अब महारानी पद्मावती सरकारी महिला महाविद्यालय, शाहजादपुर करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

बेटियों को सशक्त बनाने और हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ने की दिशा में है बड़ा कदम– शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री ने कहा कि महारानी पद्मावती का जीवन त्याग, साहस और अद्वितीय आत्मसम्मान का प्रतीक है। महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखे जाने से न केवल क्षेत्र की छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी, बल्कि वे राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक संजीदगी से समझ सकेंगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों के बलिदानों से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है। श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हरियाणा एवं बिहार के बीच शुरू होगी अंतरराज्यीय बस सेवा

दोनों राज्यों के बीच अंतरराज्यीय बस परिचालन समझौते पर हुए हस्ताक्षर

हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक शहरों से बिहार के छह प्रमंडलों तक मिलेगी सीधी बस सेवा

चंडीगढ़, । हरियाणा सरकार ने प्रदेश के यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन के लिए शुक्रवार को द्विपक्षीय बस परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते पर हरियाणा सरकार की ओर से परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा सेखर वुनडरु तथा बिहार सरकार की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त श्री आरिफ अहसन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन आयुक्त श्री अतुल द्विवेदी तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्री अतुल कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे।

इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच नियमित बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित, आरामदायक एवं गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

इन शहरों के बीच चलेगी आधुनिक एसी बस सेवा: द्विपक्षीय समझौते के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित अन्य निर्धारित शहरों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के छह प्रमंडलों–पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर–के लिए आधुनिक वातानुकूलित (एसी) बसों का नियमित परिचालन किया जाएगा। बसों का संचालन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होगा, जिससे यात्रियों को विश्वसनीय एवं समयबद्ध परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

निजी परिवहन पर कम होगी निर्भरता

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा सेखर वुनडरु ने कहा कि बिहार के साथ हुआ यह समझौता अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे यात्रियों को कम किराये पर गुणवत्तापूर्ण एसी बस सेवा उपलब्ध होगी तथा निजी परिवहन पर उनकी निर्भरता भी कम होगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य प्रदेश को देश के प्रमुख राज्यों से बेहतर एवं सुव्यवस्थित बस सेवाओं के माध्यम से जोड़ना है, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती यात्रा का लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि हरियाणा देश के प्रमुख औद्योगिक एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में से एक है। गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और अंबाला जैसे शहरों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार तथा अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विद्यार्थी, व्यापारी एवं अन्य यात्री भी नियमित रूप से दोनों राज्यों के बीच आवागमन करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह बस सेवा केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हरियाणा एवं बिहार के बीच आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक संबंधों को भी नई गति प्रदान करेगी। दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी तथा निवेश एवं पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। नियमित सार्वजनिक परिवहन सेवा दोनों राज्यों के बीच आपसी संपर्क और सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

संक्षिप्त समाचार

फर्जी गोल्ड लोन रैकेट का भंडाफोड़

नकली सोने पर बांटे 3.81 करोड़; 3 साल बैंक की आंखों में झोंकी धूल

नई दिल्ली, एजेंसी। नकली सोने के आभूषणों को असली बताकर करोड़ों रुपये का गोल्ड लोन पास करने वाले रैकेट का दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में कंपनी के ही गोल्ड अप्रेजर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रोहिणी के बुद्ध विहार के पंकज कुमार के रूप में हुई है।वह वर्ष 2014 से साई फिनकार्प प्राइवेट लिमिटेड में गोल्ड अप्रेजर के पद पर कार्यरत था।

जांच में पता चला है कि आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर 683 फर्जी गोल्ड लोन अकाउंट तैयार किए और उनके जरिए 3.81 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकाल ली।

हैरानी की बात यह है कि कंपनी को लंबे समय तक इस फर्जीवाड़े की भनक तक नहीं लगी। मामला तब सामने आया, जब इंटरनल ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी मिली।

ऑडिट में गायब मिला असली सोना

ईओडब्ल्यू के उपायुक्त अमित वर्मा के मुताबिक, गोल्ड लोन देने वाली कंपनी ने नियमित इंटरनल ऑडिट कराया था। इसी दौरान सबसे पहले करीब 14.11 लाख रुपये कीमत के असली सोने के नौ पैकेट गायब मिले। इसके बाद जब लोन खातों की गहन जांच हुई तो पता चला कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच 683 फर्जी गोल्ड लोन अकाउंट खोले गए थे। इन खातों में नकली सोने के आभूषण गिरवी दिखाकर 3.81 करोड़ का लोन जारी कर दिया गया। जांच में सामने आया कि पंकज कुमार कंपनी में गोल्ड अप्रेजर था। उसकी जिम्मेदारी गिरवी रखे गए सोने की जांच करना और उसकी शुद्धता का प्रमाण देना था।

आरोप है कि उसने इसी जिम्मेदारी का दुरुपयोग किया। वह नकली और कृत्रिम सोने के आभूषणों को असली बताकर उनकी वैल्यू तय करता था। इसके बाद फर्जी केवाईसी दस्तावेज और काल्पनिक ग्राहकों के नाम पर लोन फाइल तैयार कर दी जाती थी। इसी आधार पर करोड़ों रुपये के गोल्ड लोन जारी कर दिए गए।

ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित और उसके साथी सिर्फ फर्जी खाते बनाकर नहीं रुके। उन्होंने कंपनी की नजरों से बचने के लिए इन खातों में समय-

आप और आईवीपी से आए पार्षदों को मिला इनाम

दिल्ली भाजपा में बगावत के सुर, ; वफादार भाजपाई रह गए खाली हाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। एमसीडी के वार्ड कमेटियों के चुनाव में भाजपा आप और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी से आए पार्षदों पर खूब मेहरबान दिखी है। भाजपा ने आप और से आए पार्षदों को तीन वार्ड समितियों में चेयरमैन और तीन वार्ड समितियों में डिप्टी चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना दिया है।

वहीं, इन्हीं दोनों पार्टियों के दो पार्षदों को स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी नामांकित कर दिया। इससे करीब 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव में 27 में से आठ पार्षद वे हैं, जो आप के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन वे पहले और कुछ अभी भाजपा में शामिल हुए।

शामिल होने के बाद उन्हें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्थायी समिति का सदस्य तक का पद मिल गया। जबकि तीन बार और दो बार भाजपा के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर आए पार्षद मुंह ताकते रह गए। जिन आप से आए पार्षदों को तीन जोन में चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भाजपा ने दी है, उसमें दक्षिणी जोन में धर्मवीर सिंह, सिटी एसपी जोन से ऊषा शर्मा और रोहिणी जोन में सुमन अनिल राणा का नाम शामिल हैं।

वहीं, आप से आए तीन पार्षदों को भाजपा ने वार्ड कमेटियों के डिप्टी चेयरमैन का प्रत्याशी बना दिया है। इसमें पश्चिमी जोन में सुनील कुमार चड्ढा आप के चुनाव चिह्न पर ही चुनाव जीतकर आए थे। इसी प्रकार नरेला जोन में दिनेश भारद्वाज भी पहले आप में थे और फिर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में चले गए थे।

भाजपा में शामिल होते ही प्रत्याशी: वह शुक्रवार को सुबह भाजपा में शामिल हुए और दोपहर को भाजपा ने उन्हें नरेला जोन में डिप्टी चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना दिया। मध्य जोन में भी आप से आए प्रवीण कुमार को भाजपा ने डिप्टी चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना दिया है। इसी प्रकार स्थायी समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति में सदस्य पद पर जाने वालों में मध्य जोन से हेमचंद्र गोयल का नाम है। वह

आप से में गए थे और भाजपा में शुक्रवार की सुबह ही शामिल हुए थे।

शामिल होने के दो घंटे बाद भाजपा ने उन्हें स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित कर दिया। इसी प्रकार नरेला जोन में आप से आए पवन सहरावत को भी भाजपा ने स्थायी समिति में सदस्य बनाकर भेजा है। हालांकि, सहरावत को भाजपा ने इनाम दिया है, क्योंकि सहरावत के वोट के कारण ही वर्ष 2023 में हुए स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में भाजपा अपने तीन सदस्य जिताने में कामयाब हुई थी। भाजपा के पार्षद वैसे तो आप से आए पार्षदों को निगम में जिम्मेदारी मिलने से नाराज हैं, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले भी भाजपा ने कई आप और कांग्रेस के नेताओं को टिकट दे दिया था और अब आप से आए पार्षदों को लगातार तवज्जो दी जा रही है। एक भाजपा के वरिष्ठ पार्षद ने नाम न उजागर होने पर कहा कि दूसरे दलों के लोगों को भाजपा में शामिल कराने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि वर्षों से भाजपा में रहकर जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि आप से आए पार्षद को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो वहां पर भाजपा के पार्षदों की सुनवाई नहीं होती। जबकि आप के ही पार्षदों की सुनवाई और काम ज्यादा होते हैं। क्रॉस वोटिंग का भी है खतरा एमसीडी के वार्ड कमेटियों के चुनाव में आप व आए पार्षदों को अहमियत मिलने से भाजपा पार्षदों में नाराजगी है।

डीयू में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के चौथे साल में बदला क्रेडिट सिस्टम; नए फैसले से नाराज हुए प्रोफेसर

नई दिल्ली, एजेंसी। डीयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (यूजीसीएफ-2022) के चौथे वर्ष में रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को अधिक महत्व देने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब सातवें और आठवें सेमेस्टर में डिसर्टेशन, अकादमिक प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक के लिए पहले के छह की जगह 10-10 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं।

दोनों सेमेस्टर के मिलाकर 20 क्रेडिट

इस तरह दोनों सेमेस्टर मिलाकर इन ट्रैक के कुल क्रेडिट 20 हो जाएंगे। वहीं इस निर्णय का इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक) ने विरोध किया है। इंटेक के चेयरमैन पंकज गर्ग का कहना है कि शिक्षण कार्यभार में होने वाली 8 क्रेडिट की कमी के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के तहत दो कोर पाठ्यक्रमों को समाप्त कर उनके स्थान पर रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्रेडिट 12 से बढ़ाकर 20 निर्धारित किए गए हैं और रिसर्च के क्रेडिट कार्यभार में शामिल नहीं किए जाते हैं। इस परिवर्तन से शिक्षण कार्यभार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा अनावश्यक रूप से शिक्षकों के पदों में कमी आने की आशंका है। विश्वविद्यालय को तत्काल निर्णय लेते हुए डिसर्टेशन-प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित 20 क्रेडिट को शिक्षण कार्यभार की गणना में शामिल करना चाहिए, ताकि शिक्षण कार्यभार सुरक्षित रहे और किसी भी शिक्षक के पद पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

नई व्यवस्था के तहत चौथे वर्ष में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर (डीएससी) के कुछ पाठ्यक्रमों को डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (डीएसई) पूल में स्थानांतरित किया गया है।

छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर में तीन पाठ्यक्रम चुनने की सुविधा मिलेगी। वे तीन डीएसई, या दो डीएसई के साथ एक जनरल इलेक्टिव (जीई), अथवा एक डीएसई और दो जीई का विकल्प चुन सकेंगे।

बनी रहती है दुर्घटना की आशंका

दिल्ली में फुटपाथ पर बन रहे ईवी चार्जिंग स्टेशन, पैदल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

नईदिल्ली, एजेंसी। राजधानी के ट्रैफिक में चलना किसी दुरूह कार्य से कम नहीं। पैदल चलना उससे भी बड़ा जोखिम। हालांकि पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बने हैं, जो उनका अधिकार भी है। पर अतिक्रमण के चलते ये कई जगह सिमट गए हैं तो कई जगह पर पैदल वालों के अधिकारों पर डाका भी डाल दिया गया है। घनी आबादी वाले इलाकों और कालोनियों में जहां फुटपाथ पर पैदल चलने की जगह भी मुश्किल से है, वहां ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैट्री स्वैपिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। स्थिति यह कि सड़क पर वाहन खड़ा कर चार्जिंग करने से जाम की समस्या बढ़ रही है। दूसरी ओर पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी नहीं मिल रहा है। वहीं सड़क पर पैदल चलने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जामिया से मोदी मिल मार्ग पर सुखदेव विहार लाल बत्ती पर भी फुटपाथ पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाया है। फुटपाथ पर ही लोग वाहनों को पार्क कर चार्ज करते हैं। इसके चलते पीक समय में जहां जाम लगते हैं, वहीं छात्रों और स्थानीय निवासियों को पैदल चलने में दुश्वारी होती है। वर्तमान में दिल्ली में 8998 चार्जिंग प्वाइंट हैं, जबकि आवश्यकता 36,177 तक की है। सरकार दिसंबर तक चार्जिंग प्वाइंट की संख्या 16,070 तक बढ़ाने में लगी है। सार्वजनिक उपक्रम और निजी बिजली कंपनियों को ईवी चार्जिंग स्टेशन

लगाने अनुमति दी गई है। वहीं, एमसीडी ने अलग-अलग हिस्सों में जमीन उपलब्ध कराने के साथ सार्वजनिक पार्किंग में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की छूट दी है। मेट्रो स्टेशनों के आस-पास चार्जिंग स्टेशन बनाने में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड सहयोग कर रहा है।

ट्रांसको के मुताबिक जहां भी स्टेशन बनाए जाते हैं, वहां वाहनों को खड़ा करने की जगह का ध्यान रखा जाता है। उपलब्ध स्थान पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाया जाता है।

48.42 से अधिक चालान किए गए जारी

दिल्ली के 8 प्रमुख कॉरिडोर हुए सिग्नल-फ्री, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंजीनियरिंग, तकनीक और जनभागीदारी पर आधारित कई नई पहल शुरू की हैं। 25 प्रमुख कारिडोर के अध्ययन के बाद आठ कारिडोर को सिग्नल-फ्री बनाया गया है।

इनमें छह उत्तरी रेंज और दो पूर्वी रेंज के हैं। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सुगम हुई है और यात्रा का समय भी कम हुआ है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने 1,200 से अधिक डीटीसी चालकों और 300 होमगार्ड्स को सड़कों पर तैनात किया है। यातायात पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल के मुताबिक, सिग्नल-फ्री कारिडोर तैयार करने के लिए गैर-जरूरी ट्रैफिक सिग्नल हटाए गए, यू-टर्न की नई व्यवस्था की गई, अनधिकृत मीडियन कट बंद किए गए और कई चौराहों का पुनर्विकास किया गया। इसका सकारात्मक असर एनएसपी से रिठाला मेट्रो स्टेशन और विकास मार्ग (लक्ष्मी नगर-करकरी मोड़) जैसे मार्गों पर देखने को मिला है। अधिकारी के मुताबिक, अन्य कारिडोर को भी चरणबद्ध तरीके से सिग्नल-फ्री बनाने का काम जारी है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई तेज की गई है। एक जनवरी से अब तक विभिन्न उल्लंघनों के लिए 48,42,953 चालान जारी किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 47,52,173 चालान हुए थे। रेड लाइट उल्लंघन और ओवरस्पीडिंग का पता लगाने वाली तकनीक के माध्यम से 17,21,221 ई-चालान जारी किए गए। वहीं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामलों में 2,187 एफआइआर दर्ज की गई हैं। जाम वाले स्थानों पर सुधार के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनएचएआइ, डीएमआरसी और

डीटीसी के साथ मिलकर कई इंजीनियरिंग उपाय लागू किए हैं। कश्मीरी गेट आइएसबीटी पर अतिरिक्त बस बे और पैदल यात्रियों की सुविधाएं विकसित की गईं, मजनू का टीला पर फुटओवर ब्रिज बदला गया, आनंद विहार आइएसबीटी पर पिक-अप और ड्राप-आफ जोन बनाए गए और अधचीनी गांव, आश्रम चौक और अन्य स्थानों पर बस स्टैंडों का पुनर्स्थापन किया गया। इन उपायों से कई प्रमुख जंक्शनों पर जाम में कमी आई है।

द्वारका को निवेश का बड़ा हब बनाने की तैयारी, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने निवेशकों से की चर्चा

निवेश के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर उभरने की अनूठी स्थिति में है

नईदिल्ली, एजेंसी। कुतुब गोल्फ कोर्स परिसर में बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने विकसित दिल्ली को लेकर निवेशकों संग संवाद किया। इस दौरान द्वारका को एक बड़े आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र के तौर पर विकसित करने के उपायों पर चर्च की गई। उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि एशिया के सबसे बड़े नियोजित उप-नगरों में से एक होने के नाते, द्वारका निवेश के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर उभरने की अनूठी स्थिति में है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास होना, बेहतरीन कनेक्टिविटी और विकसित होता शहरी इकोसिस्टम मिलकर इसे अलग-अलग सेक्टर में निवेश के लिए तैयार करते हैं, जिससे कामर्स, हास्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अवसर पैदा होते हैं। निवेशकों ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इनोवेशन सुविधाओं, एक सुव्यवस्थित सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और आसान अनुमोदन प्रक्रियाओं के ज़रिए द्वारका और दिल्ली में निवेशकों के लिए ज़्यादा अनुकूल इकोसिस्टम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हास्पिटैलिटी, टूरिज्म और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, नॉलेज-बेस्ड इंडस्ट्रीज़, आइटी, आइटीईएस और जीसीसीएस को प्रोत्साहन देने, रिसर्च और डेवलपमेंट को मजबूत करने, पर्याप्त होटल क्षमता के साथ यशोभूमि और भारत मंडपम जैसे एमआइसीई इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने की जरूरत पर भी जोर दिया। निवेशकों की ओर से मिले

रचनात्मक सुझावों पर उपराज्यपाल ने कहा कि शहरी जरूरतों के अनुसार फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) सहित योजना और विकास के नियमों की समीक्षा करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर दिल्ली की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सेक्टर-विशिष्ट नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ''ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस'' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रशासन एक पारदर्शी, कुशल और निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जिससे सतत विकास को गति मिलेगी, रोजगार सृजित होगा और ''विकसित दिल्ली'' की ओर दिल्ली के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

10वीं-12वीं में दूसरे चरण के दाखिले का दूसरा मौका

नई दिल्ली, एजेंसी। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 10वीं और 12वीं में गैर-योजनाबद्ध प्रवेश का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला किया है। पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को अब सामान्य प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण के जरिए प्रवेश का अवसर मिलेगा। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के अनुसार, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र 10 जुलाई से मिलने शुरु हो गए हैं और 25 जुलाई तक जमा किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा एक अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी, जबकि परिणाम पांच अगस्त को घोषित किया जाएगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह मौका केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहले चरण में आवेदन नहीं कर सके थे। प्रवेश केवल दिल्ली के निवासियों को मिलेगा। और दाखिले शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों में होंगे।

दिल्ली में 1 अगस्त से महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर नया नियम, बिना पिंक सहेली कार्ड देना होगा किराया

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार द्वारा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद्र एक अगस्त से दिल्ली में महिला यात्री मुफ्त बस सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगी। महिला यात्रियों द्वारा पिंक सहेली कार्ड को अपनाने की धीमी गति को देखते हुए, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपनी बसों में एक विशेष अभियान भी शुरू किया है, जिसमें महिलाओं को कार्ड बनवाने की सलाह दी गई है। डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक एक अगस्त से, पिंक टिकट केवल उन महिला यात्रियों को जारी किए जाएंगे जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है, जिसे उन्हें बस में चढ़ते समय टैप करना होगा। ये महिला यात्री योजना की शर्तों के अनुसार मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाना जारी रख सकेंगी। अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा कागज आधारित पिंक टिकट को धीरे-धीरे बंद करने और मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणाली पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए एक अगस्त से, जिन महिला यात्रियों के पास पिंक सहेली कार्ड नहीं है, उन्हें पिंक टिकट जारी नहीं किए जाएंगे और उन्हें डीटीसी और परिवहन विभाग (क्लस्टर) की बसों में यात्रा करने के लिए लागू किराया देकर सामान्य टिकट खरीदना होगा।

7 साल में साफ होगी दिल्ली की हवा 8300 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली को जानलेवा प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अब तक की सबसे बड़ी सात वर्षीय कार्ययोजना तैयार की है। ''स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली'' नाम के इस मेगा प्रोजेक्ट पर कुल 8,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके तहत वर्ल्ड बैंक 65 प्रतिशत राशि लोन के रूप में देगा, जबकि बची हुई 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार खुद वहन करेगी। शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की ओरिएंटेशन कार्यशाला का शुभारंभ किया, जहां वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड पाल प्रोसी ने सीएम को वित्तीय ग्रांट सुविधा की औपचारिक मंजूरी का पत्र सौंप दिया। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2026 से शुरू होकर अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू रहेगा। सरकार का दावा है कि इस भारी-भरकम बजट का इस्तेमाल तात्कालिक राहत के लिए नहीं, बल्कि राजधानी की हवा को हमेशा के लिए साफ करने के दीर्घकालिक और वैज्ञानिक ढांचे पर किया जाएगा। सड़कों से हटेंगे पुराने वाहन, बढ़ेगी निगरानी प्रदूषण को जड़ से खत्म करने के लिए इस योजना को दो मुख्य मोर्चों पर लागू किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर कड़ा प्रहार होगा। इसके तहत दिल्ली की सड़कों से बेहद पुराने और अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। मजबूत किया जाएगा। साथ ही, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और कचरा प्रबंधन के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।

दूसरी तरफ, प्रदूषकों पर नजर रखने के लिए एक अत्याधुनिक ''इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर'' और आधुनिक एयर क्वालिटी मानिटरिंग नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे डेटा के आधार पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेण्डर नं.: पीआरवाईजे-सिग-017-2026-27 दिनांक: 09.07.2026

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियन्ता /समन्वय / उत्तर मध्य रेलवे/ प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एंव उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्य के लिये ई- निविदा निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक **07.08.2026** को **12:00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है । **कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।**

क्रम सं. 1, निविदा नं.: पीआरवाईजे-सिग-017-2026-27, **कार्य का विवरण :** प्रयागराज डिवीजन में दो साल के लिए डेटाकॉम इक्विपमेंट - एसटीएम, मक्स आदि का सालाना रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट ।

अनुमानित मूल्य (₹) : 1,06,86,243/- **बिड सिक्योरिटी (₹):** 2,13,700/-

निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹): 0/-, कार्य समापन की अवधि: 24 माह,**निविदा बन्द होने की तिथि: 07.08.2026, 2. निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता:** निविदा प्रपत्र **www.ireps.gov.in** पर निविदा खुलने की तिथि से 21 दिन पहले उपलब्ध हो जायेंगे। **3. निविदा खुलने का समय, तिथि तथा स्थान:** निविदा पूर्व निर्धारित तिथि को **12:30 बजे** या उसके बाद ई-निविदा द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक, प्रयागराज के कार्यालय में खोली जायेगी। अगर उस दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहे तो निविदा अगले दिन, कार्य दिवस पर खोली जायेगी। **1573/26 (D)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

उत्तर रेलवे

ई–नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/यात्री सेवा, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल, नई दिल्ली द्वारा पे एंड यूज शौचालय ROMT & MOT के आधार पर अनुबंध लॉट्स/साइट्स के आवंटन हेतु ई–नीलामी, IREPS पोर्टल **(https://ireps.gov.in/)** पर पालमई–बोली "जैसा है जहां है" के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है

ई–कैटलॉग संख्या	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	रेलवे स्टेशन/स्थान/साइट
PaynUse-8-2026	दिनांक 27.07.2026 को 12:00 बजे	हज़रत निज़ामुद्दीन (NZM) 02 साइट्स, पानीपत (PNP) 01 साइट, पटेल नगर (PTNR) 01 साइट, दिल्ली (DLI) 01 साइट, नरवाना (NRW) 1 साइट, मानसा (MSZ) 01 साइट, जींद (JIND) 1 साइट & आनंद विहार (ANVT) 01 साइट कुल–9 साइट्स/स्थल।
वेबसाइट विवरण जहां ई–नीलामी दस्तावेज का पूरा विवरण देखा जा सकता है।	https://ireps.gov.in/	
ई–नीलामी में भाग लेने के लिए ठेकेदारों के लिए पूर्वापेक्षाएं	**आईआरईपीएस के ई–नीलामी लीजिंग मॉड्यूल के माध्म से आयोजित ई नीलामी में भाग लेने के इच्छुक सभी ठेकेदारों को अपनी बोलियां जमा करने से पहले निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:** • ई– नीलामी लीजिंग मॉड्यूल के लिए आईआरईपीएस पर पंजीकरण– ई–नीलामी लीजिंग मॉड्यूल के लिए सक्रिय आईआरईपीएस उपयोगकर्ता खाता; एकमुश्त पंजीकरण शुल्क का भुगतान; भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता; आईआरईपीएस खाते के साथ एस बी आई बैंक खाते का एकीकरण; फंड का लियन मार्किंग; कारोबार का अद्यतन विवरण; जिन ठेकेदारों के पास आईआरईपीएस के किसी भी मॉड्यूल के लिए आईआरईपीएस खाता नहीं है, वे आईआरईपीएस होम पेज पर नए विक्रेताओं/ठेकेदारों (ई–निविदा/ई–नीलामी लीजिंग) लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण के लिए अपना ऑन लाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। ई–ऑक्शन लीजिंग मॉड्यूल के लिए अब वर्चुअल अकाउंट नंबर (वीएएन) नामक एक नया तंत्र शुरू किया गया है, जिसका उपयोग बोलीदाताओं द्वारा लियन मार्किंग तंत्र के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बोली लगाने हेतु प्रवेश करने से पहले किसी भी समय लियन मार्किंग मैकेनिज्म (यदि सक्रिय हो) और वैन मैकेनिज्म के बीच स्विच करने के लिए स्वतंत्र हैं। VAN तंत्र के लिए बोली लगाने वाले का भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता होना आवश्यक नहीं है। उपयोगकर्ता किसी भी बैंक में अपने किसी भी मौजूदा बैंक खाते से अपने VAN खाते में धन स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो उन्हें IREPS ई–नीलामी में भाग लेने में सक्षम बनाता है।	
संबंधित जानकारी हेतु रेलवे प्राधिकारी	वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक/ पीएस, डीआरएम कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055 **E-Mail: sanitationcell@gmail.com** **Tel.:011-23743084**	

संख्या.: 7PUB/TN/Pay&Use Toilets/Auction/2022 दिनांक: 10.07.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2387/2026

संपादकीय

सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, भरोसे का है

राम मंदिर का दर्शन और वहां दान करना करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। मगर इस समूचे मामले की वजह से आम लोगों के भीतर न्यास को लेकर एक तरह का अविश्वास पैदा हुआ है। राम मंदिर की पृष्ठभूमि में दानपात्र, रुपये, वित्तीय दस्तावेज और आवर्धक लेंस (मैग्निफाइंग ग्लास) दर्शाती फीचर इमेज, जो राम मंदिर न्यास में कथित गबन, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को दर्शाती है।राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास में कथित गबन का मामला जब से सामने आया है, तभी से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के समांतर एक संपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी संभव न हो सके।विडंबना यह है कि इस मामले के खुलासे के बाद जहां न्यास के दायरे में जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, वहां शुरू से आरोपों की दिशा भ्रमित करने की कोशिश होती रही। अब सोमवार को न्यास की एक अहम बैठक के दौरान इसके महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए और अंतरिम व्यवस्था के तौर पर एक अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई।निश्चित तौर पर यह कदम विवाद के बीच जिम्मेदारी और आरोपियों के प्रति नरमी बरतने को लेकर उठते गंभीर सवालों की तीव्रता को कम करने की एक कवायद है, लेकिन इस बीच जैसी असहज करने वाली स्थितियां पैदा हुईं, उसने आम लोगों के भरोसे को कमजोर ही किया है।इस संबंध में अब तक सामने आए आरोप-प्रत्यारोपों के बाद स्थिति इतनी उलझ गई है कि जब तक विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक एक तरह की अस्पष्टता कायम रहेगी।विडंबना यह है कि न्यास के जिन लोगों पर इसके वित्त की निगरानी, उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसकी संपत्तियों की रक्षा करने का दायित्व था, या तो उनके लिए ये तकाजे गैर-महत्त्वपूर्ण थे या फिर वे ही कठघरे में खड़े दिखे।सवाल है कि आरोपों की अनदेखी करके क्या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा सकता है! इतने समय तक किसकी देखरेख या संरक्षण में चढ़ावे की चोरी करने वालों का धंधा बेरोक-टोक चलता रहा? क्या यह उन तमाम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, जिनकी आस्था की बुनियाद पर ही न्यास का समूचा कामकाज टिका हुआ है?लोगों के भरोसे को ताक पर रखकर पैसों का गबन करने की हरकत कैसे संभव हुई? अब यह देखने की बात होगी कि इस अनियमितता के वास्तविक आरोपियों को कानून के कठघरे में खड़ा करके सजा दिलाई जाती है या नहीं?हालांकि न्यास के नए महासचिव का कहना है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से सिर्फ इस्तीफा इस मामले का हल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार कानून के दायरे में एक परिभाषित अपराध है, तो उसके लिए सजा भी निर्धारित है।

प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण दिया जाना भी इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि रहा। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मोदी ने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा लोकतांत्रिक परंपराओं तथा सभ्यतागत रिश्तों को समर्पित किया। यह सम्मान बताता है कि दुनिया में भारत की साख पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच दुर्लभ खनिज, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला और दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों पर हुए समझौते भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बेहद अहम हैं। आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन के लिए दुर्लभ खनिजों की भूमिका निर्णायक होगी। ऐसे में भारत का इंडोनेशिया के साथ इस क्षेत्र में साझेदारी करना दूरगामी रणनीतिक सोच का परिचायक है। देखा जाये तो भारत अब दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह विकास, लोकतंत्र, सुरक्षा और सांस्कृतिक शक्ति का ऐसा संगम है जो वैश्विक व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।

इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा खेल, इंडो पेसीफिक के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिये

(नीरज कुमार दुबे)

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिस दृढ़ता से कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के मार्ग पर चलता है, वह सीधे तौर पर उस वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर इशारा था जहां कई ताकतें समुद्री इलाकों पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं।

भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बदलती वैश्विक राजनीति में दोनों देश केवल पुराने मित्र नहीं, बल्कि भविष्य के रणनीतिक साझेदार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को नई मजबूती दी है। जकार्ता में जिस गर्मजोशी और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, उसने साफ संकेत दिया कि भारत अब एशिया की राजनीति, सुरक्षा और विकास की दिशा तय करने वाली प्रमुख शक्ति बन चुका है। देखा जाये तो प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा लोकतंत्र, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की मजबूत नींव भी साबित हुई।

इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहा। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया को केवल दो देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जुड़े सभ्यतागत साझेदार बताया। रामायण, महाभारत, नालंदा और प्रम्बानन मंदिर का उल्लेख करते हुए मोदी ने साफ कहा कि समुद्र ने दोनों देशों को कभी अलग नहीं किया, बल्कि यही समुद्र दोनों को जोड़ने वाला पुल बना। उनका यह संदेश केवल सांस्कृतिक संदेश नहीं था, बल्कि इंडो पैसिफिक की नई भू-रणनीतिक सोच का संकेत भी था।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिस दृढ़ता से कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के मार्ग पर चलता है, वह सीधे तौर पर उस वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर इशारा था जहां कई ताकतें समुद्री इलाकों पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं। मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और इंडोनेशिया यदि साथ खड़े होते हैं तो लोकतंत्र पर दुनिया का भरोसा और मजबूत होगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडो

पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है।

इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच हुए 20 ऐतिहासिक समझौते रहे। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, दुर्लभ खनिज, दूरसंचार, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल ढांचा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए ये समझौते आने वाले वर्षों में भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाले हैं। सबसे अधिक चर्चा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर हुए समझौतों की रही। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक संतुलन को मजबूत करने वाला कदम है।

देखा जाये तो भारत द्वारा इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित इंडोनेशिया वैश्विक समुद्री व्यापार का अहम केंद्र है। दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के तटरक्षक बलों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ना सीधे तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह साझेदारी समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों और किसी भी प्रकार की आक्रामक विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में महा सागर दृष्टि का उल्लेख करते हुए साफ कहा कि भारत मुक्त, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक चाहता है। यह संदेश पूरी दुनिया और खासतौर पर चीन के लिए था कि भारत किसी गुट की राजनीति नहीं बल्कि संतुलित और स्थिर वैश्विक व्यवस्था का समर्थक है। आसियान की केंद्रीय भूमिका पर भारत का जोर यह भी दिखाता है कि नई दिल्ली दक्षिण पूर्व एशिया को केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी मानती है।

हम आपको बता दें कि मोदी की इस यात्रा में तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में हुए समझौते भी बेहद महत्वपूर्ण रहे। भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के आधार पर इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क की शुरुआत, भुगतान प्रणाली को जोड़ने की तैयारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्टार्टअप सहयोग पर सहमति इस बात का संकेत है कि भारत अब तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु का परिसर इंडोनेशिया में खोलने का फैसला शिक्षा और ज्ञान कूटनीति के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को अपनाया है। उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि उन्हें खुशी है कि इन योजनाओं पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन इस हल्के फुल्के बयान के भीतर भारत के विकास मॉडल की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का बड़ा संदेश छिपा था। इंडोनेशिया द्वारा भारत की कृषि तकनीक, सूखी जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयोग और जनकल्याण योजनाओं का अध्ययन यह दिखाता है कि दुनिया अब भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि समाधान देने वाले राष्ट्र के रूप में देख रही है। राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण दिया जाना भी इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि रहा। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मोदी ने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा लोकतांत्रिक परंपराओं तथा सभ्यतागत रिश्तों को समर्पित किया। यह सम्मान बताता है कि दुनिया में भारत की साख पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।

साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच दुर्लभ खनिज, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला और दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों पर हुए समझौते भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बेहद अहम हैं। आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन के लिए दुर्लभ खनिजों की भूमिका निर्णायक होगी। ऐसे में भारत का इंडोनेशिया के साथ इस क्षेत्र में साझेदारी करना दूरगामी रणनीतिक सोच का परिचायक है। देखा जाये तो भारत अब दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह विकास, लोकतंत्र, सुरक्षा और सांस्कृतिक शक्ति का ऐसा संगम है जो वैश्विक व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।

बहरहाल, मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने भारत को रक्षात्मक सोच से निकालकर निर्णायक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में पहुंचा दिया है। कभी केवल दक्षिण एशिया तक सीमित माना जाने वाला भारत आज इंडो पैसिफिक की धुरी बन चुका है। दुनिया के बड़े राष्ट्र भारत के साथ साझेदारी को अपनी रणनीतिक आवश्यकता मान रहे हैं। इंडोनेशिया यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव, सामरिक दूरदृष्टि और वैश्विक प्रभाव का नया अध्याय लिख रही है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

चिता आंदोलन :मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पर मोहन सरकार की बेरुखी

(पवन वर्मा-विनायक फीचर्स)

25 दिसंबर 2024, खजुराहो की ऐतिहासिक धरती, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का अवसर, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। देशभर से आए संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि और हजारों लोगों के बीच उन्होंने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भूमिपूजन किया। प्रधानमंत्री ने इसे केवल एक बांध या सिंचाई परियोजना नहीं बताया, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने वाली योजना कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह उनकी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जो बुंदेलखंड की दशकों पुरानी प्यास बुझाएगी और इस क्षेत्र की तकदीर बदल देगी। मंच पर विकास के बड़े-बड़े दावे थे। करोड़ों लोगों के बेहतर भविष्य की तस्वीर खींची जा रही थी। इस समय का मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था। परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम को कवर करने भोपाल से खजुराहो गया था। अपार जनसमूह के बीच इस परियोजना पर बात करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर तेज देखते ही बनता था। शायद उस वक़्त उन्हें उम्मीद होगी कि उनका प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने जा रहा है, लेकिन महज डेढ़ वर्ष बाद उसी परियोजना की पहचान विकास नहीं, बल्कि 'चिता आंदोलन' बनती दिखाई दे रही है। भारी बारिश के बीच पानी में खड़े आदिवासी किसान, आसपास से लकड़ियां बटोरकर प्रतीकात्मक चिता तैयार करते लोग और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते परिवार,ये दृश्य किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होने ही चाहिए। पहली नजर में ही लगता है कि यह केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने का प्रतीक है, जो इस परियोजना के साथ लोगों के मन में जगाया गया था। सरकार दावा करती है कि यह परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगी। इसमें दो चरण होंगे और इसे पूरा होने में लगभग आठ वर्ष लगेंगे। पहले चरण में पन्ना जिले में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा दौधन बांध बनाया जाएगा। 221 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, सागर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी और दतिया सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों को इसका लाभ मिलेगा। इन आंकड़ों को सुनकर यह परियोजना हर दृष्टि से ऐतिहासिक परियोजना लगती है। लेकिन इन चमकदार आंकड़ों के पीछे एक दूसरा सच भी है। इस परियोजना की सबसे बड़ी कीमत वे आदिवासी परिवार चुका रहे हैं, जिनकी जमीन, खेत, जंगल और गांव जलाशय में समा जाएंगे। विकास की इस पूरी कहानी में सबसे कमजोर पक्ष वही लोग बन गए हैं, जिनके जीवन पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है।

छतरपुर जिले के दौनी सहित प्रभावित गांवों के लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुनर्वास को लेकर उन्हें लगातार भ्रम में रखा गया। पहले पांच लाख रुपये की सहायता तय थी। लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने पन्ना जिले के लिए अतिरिक्त 202.50 करोड़ रुपये मंजूर कर पुनर्वास पैकेज बढ़ाकर 12 लाख 50 हजार रुपये कर दिया। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है। लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि केवल राशि घोषित कर देने से पुनर्वास पूरा नहीं हो जाता। उन्हें रहने योग्य जमीन चाहिए, खेती का विकल्प चाहिए, रोजगार चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए और यह भरोसा चाहिए कि उनका भविष्य उजड़ने वाला नहीं है। यही वह बिंदु है, जहां मध्य प्रदेश सरकार सबसे कमजोर दिखाई देती है।

केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री स्वयं इसका भूमिपूजन करते हैं। करोड़ों रुपये स्वीकृत होते हैं। लेकिन पुनर्वास जैसी सबसे संवेदनशील जिम्मेदारी राज्य सरकार के हिस्से आती है। यदि पुनर्वास ठीक ढंग से होता, प्रभावित लोगों से लगातार संवाद होता और प्रशासन उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करता, तो शायद आज पानी के बीच खड़े होकर 'चिता आंदोलन' करने की नौबत नहीं आती।

किसी भी बड़ी परियोजना में विरोध होना असामान्य नहीं है। लेकिन यह विरोध जब इस स्तर तक पहुंच जाए कि लोग अपने जीवित रहते अपनी ही चिता का प्रदर्शन करने लगे,ऐसे में इसे केवल एक साधारण नागरिक की पीड़ा की पराकाष्ठा माना जाना चाहिए। यदि कोई प्रशासन सामान्य नागरिकों की पीड़ा को न समझ सके तो फिर यह शासन की संवेदनहीनता पर आरोप-पत्र बन जाता है।

सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास स्वयं खनिज, राजस्व और प्रशासन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विभागों की प्रत्यक्ष निगरानी है। ऐसी परियोजनाओं की समीक्षा नियमित रूप से होती है। प्रभावित गांवों की स्थिति, आंदोलन की जानकारी और प्रशासनिक रिपोर्टें लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंचती होंगी। फिर भी यदि आंदोलन चार दिन से अधिक चलता है, आदिवासी परिवार पानी में उतरकर प्रदर्शन करते हैं और सरकार की ओर से कोई प्रभावी पहल दिखाई नहीं देती, तो इसे केवल प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि राजनीतिक उदासीनता भी मानी जाएगी।

जब नागरिक व्यवस्था से नहीं, व्यवस्था नागरिकों से दूर होने लगे

भारत में 'एग्जिट' की यह प्रवृत्ति सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक संरचनात्मक चुनौती बन जाती है। जब मध्यवर्गीय परिवार निजी विकल्पों की ओर बढ़ते हैं, तो वे अनजाने में सार्वजनिक सेवाओं पर निर्भरता कम कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप उन सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक सामाजिक दबाव घटने लगता है। शहरी भारत में अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार जल शुद्धिकरण उपकरणों का उपयोग करते हैं। निजी विद्यालयों में नामांकन पिछले वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिकों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय कुल स्वास्थ्य खर्च का आधे से अधिक है।

(अमित कुमार)

एक व्यक्ति दो अलग-अलग रास्तों के बीच खड़ा है। एक ओर आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी व्यवस्था दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी ओर जर्जर बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं पर निर्भर क्षेत्र का दृश्य है। यह सार्वजनिक व्यवस्था और निजी विकल्पों के बीच बढ़ती खाई को दर्शाने वाली प्रतीकात्मक तस्वीर है।

भारत में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा अक्सर शिकायतों के स्वर में सुनाई देती है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन शिकायतों के बीच समाज किस प्रकार व्यवहार करता है। भारतीय मध्यवर्ग ने एक विशिष्ट रास्ता चुन लिया है। वह व्यवस्था की कमियों से टकराने के बजाय उनसे बच निकलने की कला में दक्ष होता जा रहा है। पेयजल खराब हो, तो घर में जल शुद्धिकरण यंत्र लग जाता है।

बिजली अनियमित हो तो इन्वर्टर व्यवस्था संभाल लेता है। सरकारी विद्यालयों पर भरोसा कम हो, तो निजी शिक्षा की ओर रुख कर लिया जाता है। यह प्रवृत्ति केवल सुविधा का चयन नहीं है। यह एक गहरे सामाजिक अनुबंध का संकेत है, जिसमें सार्वजनिक नागरिक व्यवस्था से दूरी बनाकर अपने लिए अलग रास्ते तैयार कर लिए जाते हैं।

इस व्यवहार को समझने के लिए अर्थशास्त्री अल्बर्ट ओ. हिर्शमैन द्वारा प्रतिपादित विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी' में प्रस्तुत किया है। जब किसी संस्था या व्यवस्था की गुणवत्ता गिरती है, तो उसके सदस्य या उपभोक्ता दो प्रमुख प्रतिक्रियाएं देते हैं। एक प्रतिक्रिया होती है व्यवस्था से बाहर निकल जाना, जिसे उन्होंने 'एग्जिट' कहा।

दूसरी प्रतिक्रिया होती है उसी व्यवस्था के भीतर रहकर सुधार की मांग करना, जिसे उन्होंने 'वॉइस' कहा। उनके विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जब 'एग्जिट' सरल और सुलभ हो जाता है, तो 'वॉइस' कमजोर पड़ जाती है। भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा इसी सिद्धांत का

जीवंत उदाहरण पेश करता है।

भारत में 'एग्जिट' की यह प्रवृत्ति सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक संरचनात्मक चुनौती बन जाती है। जब मध्यवर्गीय परिवार निजी विकल्पों की ओर बढ़ते हैं, तो वे अनजाने में सार्वजनिक सेवाओं पर निर्भरता कम कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप उन सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक सामाजिक दबाव घटने लगता है। शहरी भारत में अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार जल शुद्धिकरण उपकरणों का उपयोग करते हैं। निजी विद्यालयों में नामांकन पिछले वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिकों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय कुल स्वास्थ्य खर्च का आधे से अधिक है।

भारतीय संदर्भ में यह तथ्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जहां निजी समाधान उपलब्ध हैं, वहां नागरिक अपेक्षाकृत शांत रहते हैं, लेकिन जहां निजी विकल्प संभव नहीं हैं, वहां असंतोष मुखर हो उठता है। सड़कें खराब हों या वायु प्रदूषण बढ़ जाए, ऐसे मुद्दों पर विरोध अधिक दिखाई देता है, क्योंकि इन समस्याओं से व्यक्तिगत स्तर पर बाहर निकलना संभव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं।

स्वीडन और नार्वे जैसे देशों ने सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इस स्तर तक सुदृढ़ किया है कि अधिकांश नागरिक उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। सिंगापुर ने आवास और शहरी ढांचे के क्षेत्र में ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था विकसित की है, जिसमें बड़ी आबादी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत रहती है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा व्यापक रूप से नागरिकों की पहली पसंद बनी हुई है।

इन उदाहरणों में एक समान तत्त्व दिखाई देता है कि सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता इतनी विश्वसनीय है कि उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता सीमित हो जाती है।

भारत में स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहां निजी समाधान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यह परिस्थिति एक प्रकार की मौन सहमति को जन्म देती है, जिसमें नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ़ लेते हैं और राज्य पर सुधार का दबाव सीमित हो जाता है। हिर्शमैन ने अपनी पुस्तक में यह संकेत दिया था कि अगर किसी व्यवस्था में वफादारी का तत्त्व कमजोर हो जाए, तो 'एग्जिट' की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति विश्वास का क्षरण इसी दिशा की ओर संकेत करता है। जो लोग निजी समाधान वहन कर सकते हैं, वे अपेक्षाकृत सुविधाजनक जीवन जीते हैं, जबकि जो ऐसा नहीं कर सकते या जिनके पास विकल्प नहीं होता, वे उसी सार्वजनिक व्यवस्था में फंसे रहते हैं, जिसकी गुणवत्ता लगातार गिरती जाती है।

इस प्रकार 'एग्जिट' केवल व्यक्तिगत राहत का माध्यम नहीं रह जाता। वह सामाजिक विभाजन को भी गहरा करता है। इस परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि समाधान किस दिशा में खोजा जाए। क्या सार्वजनिक व्यय बढ़ाना पर्याप्त होगा या नागरिकों के व्यवहार में भी परिवर्तन आवश्यक है।

हिर्शमैन के अनुसार किसी भी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि 'वॉइस' को प्रोत्साहित किया जाए और 'एग्जिट' को इस प्रकार संतुलित किया जाए कि वह 'वॉइस' को निष्प्रभावी न कर दे। इसका अर्थ यह है कि निजी विकल्पों को समाप्त किए बिना सार्वजनिक सेवाओं को सक्षम बनाया जाए।

भारत के संदर्भ में यह एक गहरी मानसिकता परिवर्तन की मांग करता है। जब तक नागरिक सार्वजनिक समस्याओं को निजी साधनों से टालने को ही समाधान मानते रहेंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया धीमी रहेगी। किसी समाज की वास्तविक प्रगति उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की गुणवत्ता में परिलक्षित होती है, न कि उसके निजी समाधानों की संख्या में।

जब सुधार या बदलाव की मांग कमजोर पड़ती है, तो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व भी क्षीण होने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय समाज इस संतुलन को स्थापित करे, जहां व्यक्तिगत सुविधा के साथ-साथ सामूहिक उत्तरदायित्व का भी समान महत्त्व हो। तभी सार्वजनिक समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में वास्तविक प्रगति संभव हो सकेगी।

संक्षिप्त समाचार

बदलाव : अब भर्ती परीक्षा के सवालों पर आयोग दो बार मांगेगा आपत्तियां, नया मॉड्यूल किया गया लागू

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अनुमोदन के बाद नवीन ऑनलाइन प्रश्नपत्र ऑब्जेक्शन मॉड्यूल लागू किया गया है। इसके तहत पहले चरण में परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा के ए-सीरीज के प्रश्नपत्र को आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का नया आपत्ति मॉड्यूल लागू कर दिया है। इसके तहत आयोग परीक्षा कराने के बाद दो बार आपत्तियों का निस्तारण करेगा। इसके बाद ही परिणाम जारी करेगा। यह मॉड्यूल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आयोग से अनुमोदन के बाद नवीन ऑनलाइन प्रश्नपत्र ऑब्जेक्शन मॉड्यूल लागू किया गया है। इसके तहत पहले चरण में परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा के ए-सीरीज के प्रश्नपत्र को आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा। अभ्यर्थी सात दिन के भीतर इससे संबंधित प्रश्नों, विकल्पों की संरचना पर निशुल्क आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों का निपटारा करने के बाद ही आयोग उत्तर कुंजी (आंसर की) जारी करेगा।इस आंसर की पर सात दिन के भीतर आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क भुगतान करके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों पर आयोग विशेष विशेषज्ञों से निपटारा कराएगा। उनकी संस्तुतियों के आधार पर अंतिम आंसर की तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट और अंतिम आंसर की एक साथ जारी होंगे। दोनों चरणों की आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएंगी। कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित भर्ती परीक्षा के प्रश्नों पर अपनी आपत्ति प्रमाण के साथ ही दर्ज कराएं।

मुद्दों को धार देने के लिए रणनीति का खींचा खाका

देहरादून, एजेंसी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई नवगठित राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दों को धार देने के लिए रणनीति का खाका खींचा गया। वहीं, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को सख्त संदेश दिया कि 2027 फतह करना है, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव ने राज्य की राजनीति के साथ जन मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नेताओं से राय ली। उन्होंने पार्टी नेताओं को चुनाव जीतने के लिए एकजुटता का मंत्र दिया। कहा, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी नेताओं को आपसी तालमेल के साथ काम करना है। 2027 में चुनाव जीतने के लिए पार्टी में अनुशासनहीनता की कोई गुंजाइश नहीं है। पार्टी में छोटे व बड़े सभी नेताओं को पार्टी लाइन पर काम कर कांग्रेस को सत्ता में लाना है। भाजपा के खिलाफ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुद्दों को प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में लेकर जाना है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, पार्टी के सभी नेताओं का लक्ष्य कांग्रेस को 2027 में सत्ता में लाना है। 2022 में भाजपा के एक झूठ से चुनाव हार गए थे। भले ही आपस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन सबका लक्ष्य पार्टी की जीत है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी है। कांग्रेस के पास कुशासन को बदलने का जज्बा है। प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को कांग्रेस से काफी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। नए लोगों में पार्टी में शामिल करने पर फोकस होना चाहिए। पिछले कई दिनों से नई दिल्ली में होने से पूर्व सीएम हरीश रावत बैठकों में नहीं पहुंच पाए।

ग्राउंड वाटर रिचार्ज की पॉलिसी बनेगी

देहरादून, एजेंसी। राज्य में भूमिगत जल स्तर को सुधारने और जल स्रोतों को जीवित रखने के लिए सरकार अब ठोस नीति बनाने जा रही है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने स्प्रिंग एंड रिवर रेज्युविनेशन अथॉरिटी(सारा) को प्रदेश के लिए एक व्यापक ग्राउंड वाटर रिचार्ज पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि इस नीति के तहत गैर सरकारी और आवासीय सोसायटियों में वर्षा जल संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) के माध्यम से भूमिगत जल को रिचार्ज करने पर विशेष फोकस किया जाएगा। बृहस्पतिवार को सचिवालय में सारा की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जल संरक्षण की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़े पौराणिक धारे-नौलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार के लिए सभी जनपद जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव भेजें। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में नदियों को पुनर्जीवित करने का काम लगातार चल रहा है लेकिन इसमें और अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एक जनपद एक नदी प्रोजेक्ट के तहत जिलों से जो भी प्रस्ताव आए हैं, उन पर तुरंत काम शुरू किया जाए। बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर काम करने की सलाह दी।

कांग्रेस के चुनावी रण में दिख रहा रणनीतिक 'खालीपन', हरदा की गैरहाजिरी का कितना प्रभाव

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे महज कुछ महीनों को राजनीतिक रणनीतियों के लिए अहम माना जा रहा है. खास बात ये है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव के लिए होमवर्क भी होने लगा है और जिम्मेदारियां भी तय की जाने लगी हैं, लेकिन राज्य स्थापना के बाद यह पहला मौका है, जब इस बेहद खास पल में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता की ही भूमिका शून्य हो गई है. दरअसल, इस बार हरीश रावत की गैरमौजूदगी में ही पार्टी रण के लिए मैदान भी चुन रही है और चुनावी रणबांकुरों का चयन भी कर रही है. इतना ही नहीं चुनाव में सभी की भूमिकाओं को तय करने के लिए भी इस वक्त पार्टी की सक्रिय राजनीति में हरीश रावत मौजूद नहीं हैं. उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कांग्रेस संगठन भी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है. यही नहीं केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रदेश का दौरा कर रहा है, जिसके जरिए कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा लंबे समय से राजनीतिक मंचों और कार्यक्रमों से दूर है. करीब 1 महीने से कहीं नजर नहीं आए हरदाः पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पिछले करीब 1 महीने से कहीं नजर नहीं आए हैं. इसके पीछे की वजह उनके खराब स्वास्थ्य को बताया गया है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी में उनको लेकर तमाम चर्चाएं जारी हैं. करीब एक महीने पहले हरीश रावत देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हुए थे. इसके बाद से वे किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम, संगठनात्मक बैठक या सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए हैं. इस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम कार्यक्रम आयोजित किए. प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेशभर में बैठकों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन इन कार्यक्रमों में हरीश रावत की कमी लगातार महसूस की गई. कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल का भी देहरादून दौरा हुआ. जिसे प्रदेश कांग्रेस के लिए इसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक माना गया, क्योंकि लंबे समय बाद वेणुगोपाल उत्तराखंड पहुंचे थे. इसके बावजूद हरीश रावत इस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए. इसके बाद अब पार्टी कार्यकर्ताओ के बीच चर्चा इस बात को लेकर रही कि क्या हरीश रावत का स्वास्थ्य ज्यादा खराब है और क्या चुनावी रणनीतियों में उनके अनुभव का लाभ पार्टी को आने वाले दिनों में मिल पाएगा या नहीं? पार्टी के नेताओं के अनुसार हरीश रावत की अनुपस्थिति का मुख्य कारण उनका स्वास्थ्य है. कुछ दिन पहले स्वयं हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का उल्लेख किया था. ऐसे में पार्टी के भीतर उनकी गैरमौजूदगी को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा रहा है, न कि किसी राजनीतिक असहमति से. कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह कहते हैं कि, हालांकि, चुनावी तैयारियों के इस दौर में हरीश रावत की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक विश्लेषण भी शुरू हो गया है. उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय तक हरीश रावत चुनावी रणनीति, संगठन और जनसंपर्क का प्रमुख चेहरा रहे हैं. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रियता और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद उनकी पहचान रहा है. हरदा की गैर मौजूदगी पर अलग-अलग रायः ऐसे में जब चुनाव नजदीक हों और वे लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हों, तो यह स्वाभाविक है कि इससे आगामी चुनाव पर इसके प्रभाव की भी बात होगी. पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग राय भी सामने आ रही है. एक वर्ग का मानना है कि हरीश रावत जल्द स्वस्थ होकर फिर से चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे और पहले की तरह कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय भूमिका निभाएंगे. वहीं, दूसरा वर्ग यह कहता है कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा और संगठन के आधार पर आगे बढ़ने वाली राजनीतिक पार्टी है. इसलिए किसी एक नेता की अस्थायी गैरमौजूदगी से चुनावी तैयारियों पर निर्णायक असर नहीं पड़ेगा. अब सबकी नजर इस बात पर है कि स्वास्थ्य में सुधार के बाद हरीश रावत कब सक्रिय राजनीति में वापसी करते हैं. वहीं 1 अप्रैल 2016 को हरीश रावत दोबारा सीएम बने , लेकिन एक दिन बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था. 11 मई 2016 को फिर से हरदा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, 18 मार्च 2017 तक वो सूबे के सीएम रहे.

शादी के सिर्फ दो महीने बाद मौत...पत्नी को सरप्राइज देने आया पति, जन्मदिन मनाकर सोया और फिर कभी नहीं उठा

नैनीताल, एजेंसी। हरिद्वार से युवक पत्नी के जन्मदिन का सरप्राइज देने घर आए थे। ड्यूटी पर लौटने के लिए उठने का समय हुआ, लेकिन वह नींद से नहीं उठे। पत्नी ने जगाने का प्रयास किया तो शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी के जन्मदिन पर सरप्राइज देने हरिद्वार से घर आए युवक की शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक तौर पर चिकित्सक इसे साइलेंट हार्ट अटैक का मामला मान रहे हैं, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है। हल्दूचौड़ (दीना डी क्लास) निवासी कमल आर्य (30) हरिद्वार स्थित हीरो कंपनी में कार्यरत था। उसकी शादी इसी वर्ष 30 अप्रैल को बिंदुखत्ता निवासी युवती से हुई थी। बृहस्पतिवार को पत्नी का जन्मदिन होने के कारण कमल विशेष रूप से छुट्टी लेकर घर आया था। रात में परिवार के साथ जन्मदिन मनाया और भोजन करने के बाद वह सो गया।परिजनों के अनुसार कमल को शुक्रवार सुबह हरिद्वार ड्यूटी पर लौटना था। इसके लिए उसे लालकुआं से सुबह छह बजे की ट्रेन पकड़नी थी। सुबह अलार्म बजने के बाद भी जब वह नहीं उठा तो पत्नी ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल हल्द्वानी स्थित डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों का प्राथमिक अनुमान है कि कमल की मौत साइलेंट हार्ट अटैक से हुई हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमल तीन भाइयों में सबसे छोटा था।

ट्रैफिक दबाव और पार्किंग की समस्या पर देहरादून डीएम सख्त, माइक्रो लेवल प्लान होगा तैयार

देहरादून, एजेंसी। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का बढ़ता दबाव और पार्किंग की समस्या को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को मोबिलिटी प्लान के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने संबंधित विभागों को शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए माइक्रो लेवल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से समयबद्ध तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारें. बैठक में आढ़त बाजार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, इंदिरा मार्केट पुनर्विकास, मंडी शिफ्टिंग, परेड ग्राउंड पार्किंग, रामराय पार्किंग और अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. डीएम ने आढ़त बाजार में यातायात सुधार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और प्रमुख चौराहों के सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. इंदिरा मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग की धीमी प्रगति पर नाराजगीः बैठक में इंदिरा मार्केट में निर्माणाधीन मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि यहां करीब 1050 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग विकसित की जा रही है. निर्माण कार्य की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और एमडीडीए अधिकारियों को कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने व निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि पार्किंग स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उपलब्ध पार्किंग का बेहतर उपयोग हो और शहर में जाम की समस्या कम हो सके. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बनेगी कार्य योजनाः जिलाधिकारी ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पुलिस अधीक्षक यातायात और नगर निगम को संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण, बेहतर पार्किंग व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू किया जाए. बैठक में मंडी शिफ्टिंग,आढ़त बाजार सड़क सुधार, परेड ग्राउंड और रामराय पार्किंग सहित अन्य लंबित परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई. वही जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि सभी विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि देहरादून की यातायात व्यवस्था को आधुनिक, व्यवस्थित और जनसुविधा केंद्रित बनाया जाएगा.

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी केसः एसआईटी खंगाल रही तीन साल का रिकॉर्ड, बैंक खातों पर भी नजर

देहरादून, एजेंसी। बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी सबूत जुटाने मे जुट गई है. सरकार और प्रशासन के लिए गले की फांस बना ये मुद्दा रोज कुछ नया लेकर आ रहा है. जिसके कारण इस मामले की जांच पर हर किसी की नजर है. जांच टीम में कौन कौन शामिलः इस जांच में चमोली पुलिस ने विवेचना के लिए पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट को एसआईटी का इंचार्ज बनाया है. बदरीनाथ थानाध्यक्ष निरीक्षक महादेव उनियाल को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. टीम में एसएसआई प्रकाश बिष्ट, लंगासू चौकी प्रभारी एसआई दिनेश पंवार और एसओजी के दो कर्मियों को भी शामिल किया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच केवल घटना की पुष्टि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे घटनाक्रम की प्रत्येक कड़ी को जोड़कर तथ्यों की वैज्ञानिक और कानूनी कसौटी पर जांच की जाएगी. शुरुवाती जांच में कई तरह के खुलासे होने की उम्मीद है. तकनीकी साक्ष्यों को लेकर भी जांचः उन्होंने बताया रिकॉर्ड काफी विस्तृत है. उसे उपलब्ध कराने में समय लग रहा है. इन दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही पुलिस आगे की कड़ियों को जोड़ पाएगी. एसआईटी की जांच तकनीकी साक्ष्यों पर भी समान रूप से केंद्रित है. पुलिस आरोपी कर्मचारी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), ई-मेल गतिविधियों और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है. इसके साथ ही वर्तमान कर्मचारियों के अलावा पिछले तीन वर्षों में बदरीनाथ मंदिर में तैनात रहे और यहां से स्थानांतरित हो चुके सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण भी तलब किया गया है. पुलिस यह समझने का प्रयास कर रही है कि संबंधित अवधि में जिम्मेदारियां किसके पास थीं. चढ़ावे के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती रही? यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्थान से जुड़ा कोई तथ्य सामने आता है तो उसे भी विवेचना में शामिल किया जाएगा. सीसीटीवी फुटेज का फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषणः मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जा रहे सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी पुलिस विशेष रणनीति पर काम कर रही है. सीओ मदन सिंह बिष्ट के अनुसार फिलहाल गढ़वाल आयुक्त स्तर पर भी इस मामले की जांच चल रही है. इसलिए पहले आयोगीय जांच के लिए फुटेज का परीक्षण पूरा होने दिया जाएगा. उसके बाद पुलिस उन्हें विधिवत सीज कर तकनीकी विश्लेषण करेगी.

उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटज की जांच बेहद समय लेने वाली प्रक्रिया होती है. कई बार एक घंटे की रिकॉर्डिंग को बारीकी से देखने में तीन घंटे या उससे अधिक समय लग जाता हैं. यही कारण है कि पुलिस किसी भी स्तर पर जल्दबाजी नहीं करना चाहती. पुलिस प्रत्येक दृश्य का सूक्ष्म परीक्षण करेगी. बीकेटीसी से मांगे गए जवाब, कर्मचारियों के भी होंगे बयानः एसआईटी ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति से घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मांगे हैं. समिति को आठ से दस बिंदुओं पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. वहीं मुकदमा दर्ज वाले कर्मचारी सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. दूसरी ओर बीकेटीसी की आंतरिक जांच टीम ने करीब फिलहाल 40 दिन पुराने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए निरीक्षण किया. चढ़ावे की गणना प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया समिति का दावा है कि उसकी आंतरिक जांच भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

अधिकारियों की लापरवाही, दूसरे के पते पर लिया कनेक्शन, कटने की बारी आई तो चला पता, जांच के आदेश

देहरादून, एजेंसी। एक व्यक्ति ने दूसरे के पते पर कनेक्शन ले किया। जब कनेक्शन कटने की बारी आई तो इस बात का पता चला। राज्य सूचना आयोग ने विभाग को अपने स्तर पर जांच करने के आदेश दिए हैं।

बिजली विभाग में अधिकारियों की लापरवाही का आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। रुड़की विद्युत वितरण खंड ने एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के आवासीय पते पर बिजली कनेक्शन जारी कर दिया। असली मालिक को इसका पता तब चला जब बिजली काटने की जानकारी उनके पते पर भेजी गई।

सूचना आयोग ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है। रुड़की के संदीप कुमार ने राज्य सूचना आयोग में एक अपील दाखिल कर बताया कि 2016 में उनके आवासीय पते पर एक बिजली कनेक्शन जारी किया गया। यह 2021 तक उपयोग में रहा। 2025 में एक नोटिस द्वारा उन्हें इस कनेक्शन के काटे जाने की जानकारी दी गई। इसके बाद ही पीड़ित को इस मामले की जानकारी हुई। संदीप कुमार ने सूचना आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बिजली कनेक्शन जारी करने के पहले भी संबंधित पते का निरीक्षण किया गया होगा। अब विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पते पर जारी बिजली कनेक्शन किसी अन्य पते पर कैसे लगा दिया गया। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसे कदाचार का मामला माना है। आयोग ने विभाग को इस मामले में अपने स्तर पर जांच करने का आदेश दिया है।

आयोग ने पीड़ित को मांगी गई सूचना दस दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।

देहरादून में संग्रह अमीनों की नियुक्ति बनी मजाक, चर्चाओं में आया डीएम का आदेश

देहरादून, एजेंसी। देहरादून में संग्रह अमीनों की नियुक्ति मजाक बन गई है. कभी इन्हें इनके मूल काम से हटाकर कलेक्ट्रेट में संबद्ध कर दिया जाता है, तो कभी शिकायत आने पर इन्हें नियमों का हवाला देकर हटा भी दिया जाता है. लेकिन इस बार दो संग्रह अमीनों की नियुक्ति का यह मामला इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि करीब 15 दिनों में ही इनमें से एक संग्रह अमीन को॒ष्ठरू केके मिश्रा अपने कार्यालय में वापस ले आये और इसके बाद देहरादून कलेक्ट्रेट में हलचल तेज हो गई.

मामला भले ही दो संग्रह अमीनों की नियुक्ति का है, लेकिन इसने जिलाधिकारी कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनाई हुई है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट में जिन अमीनों को शिकायत के बाद उनके मूल काम पर लौटाने का फैसला लिया गया. उनमें से एक संग्रह अमीन को वही नियम और आदेश भुलाते हैं, 15 दिन में वापस भी बुला लिया गया.

दरअसल राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी वाले दो संग्रह अमीन अपने मूल काम को छोड़कर अपर जिला अधिकारी केके मिश्रा के कार्यालय में संबद्ध रहे. यानी जिनका काम राजस्व संग्रह का था उन्हें व्यक्तिक सहायक के तौर पर कार्यालय में रखा गया. जबकि जिला कलेक्ट्रेट में व्यक्तिक सहायक संवर्ग अलग से है और कार्यालय में यही कर्मचारी व्यक्तिक सहायक का काम देखते हैं.जाहिर है कि सेवा शर्तों और दायित्व के अलग-अलग होने के बावजूद जिस तरह इन दो संग्रह अमीनों को अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में जिम्मेदारी दी गई, उससे कर्मचारियो में भारी रोष फैल गया.

नतीजतन व्यक्तिक सहायक संवर्ग ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की, और इसके बाद जिलाधिकारी ने नियमों को देखते हुए फौरन इन्हें हटाने के निर्देश दे दिए. संग्रह अमीन गिरीश चंद पांडे और दीपक नेगी को 25 जून 2026 को हटाने के आदेश हो गए, आदेश में साफ कहा गया कि पूर्व जिलाधिकारी और मौजूद जिलाधिकारी ने सभी संवर्गों को अपने-अपने दायित्व पर ही जिम्मेदारी दिए जाने के निर्देश दिए हैं. लेकिन कलेक्ट्रेट के ही इस आदेश की करीब 13 दिनों बाद धज्जियां उड़ा दी गई.

अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने 8 जुलाई को एक नया आदेश करते हुए संग्रह अमीन दीपक नेगी जिसको कुछ दिन पहले ही हटाया गया था उसे वापस अपने कार्यालय में फिर नियुक्ति दे दी. इस आदेश में मानसून सत्र और आपदा के कार्यों के अलावा शासकीय कार्य ज्यादा होने का हवाला दिया गया.

हालांकि इस दौरान कर्मचारी संगठन इस बात को सामने रखते रहे कि आखिरकार चिन्हित अमीन को ही कलेक्ट्रेट में क्यों नियुक्ति दी जा रही है. खास बात यह है कि अपर जिलाधिकारी का इस तरह उसी अमीन को वापस अपने कार्यालय में बुलाना कलेक्ट्रेट में चर्चा का सबक बना रहा.

बाद जिलाधिकारी आशीष चौहान तक पहुंची तो उन्होंने फौरन इस पर एक्शन ले लिया. यही नहीं अपनी नाराजगी जताते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो निर्देश जारी किए जाते हैं उसके अनुसार ही कलेक्ट्रेट में काम किए जाएं. इसका असर यह हुआ कि जिलाधिकारी की नाराजगी के बाद 24 घंटे में ही अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा को बैक फुट पर आना पड़ा और उन्होंने 10 जुलाई को अपने उस आदेश को वापस ले लिया. जिसमें उन्होंने संग्रह अमीन दीपक नेगी को अपने कार्यालय में तैनात किया था. नए आदेश में कृष्ण कुमार मिश्रा ने दीपक नेगी को अपने कार्यालय में तैनात करने वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का पत्र जारी किया.

संक्षिप्त समाचार

भाजपा नेता सुनील भराला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की भेंट

मेरठ। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। सुनील भराला ने महाकुंभ में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में प्राण-प्रतिष्ठित भगवान परशुराम की प्रतिमा एवं भगवान परशुराम चालीसा उन्हें भेंट की। इस दौरान भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा, भगवान परशुराम के आदर्शों तथा राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने राष्ट्रहित और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करने का संदेश दिया। सुनील भराला ने कहा कि भगवान परशुराम के न्याय, धर्म, तप, शौर्य और राष्ट्रसेवा के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है।

परतापुर पुलिस पर किसान की 25 बीघा फसल में जहरीला पानी छोड़ने का आरोप

मेरठ, एजेंसी। परतापुर थाना पुलिस पर किसान महेश ने उसकी 25 बीघा फसल में बिना अनुमति के नाले का केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। किसान ने सीएम पोर्टल और उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। किसान का आरोप है कि थाने में पानी न भरे, इसके लिए शुक्रवार को परतापुर थाने से दो दरोगा और एक कांस्टेबल ने उसके खेत में जहरीला पानी छोड़ दिया। इससे उसकी मूंग और ईख की 25 बीघा फसल खराब होने की आशंका है। परतापुर थाने के पास रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर एक नाला है। बरसात के कारण थाने के पीछे बनी कॉलोनी और एक केमिकल फैक्टरी का पानी इसी नाले में आता है। पिछले दो दिनों की बरसात से नाला ओवरफ्लो हो गया था, जिससे पानी थाने में भी जाने लगा। गांव कुंडा निवासी किसान महेश ने बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई अपनी मर्जी से की। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि नाला ओवरफ्लो था और घरों से पानी निकालने के लिए नाले को खोला गया था। उन्होंने कहा कि किसान के खेत में पहले से ही पानी जाता है।

अखिलेश यादव ने अनाथ बच्चों की दादी को दो लाख रुपये का चेक दिया

मेरठ, एजेंसी। ग्राम मेघराजपुर में माता-पिता की मृत्यु के बाद तीन बच्चों की परवरिश उनकी बुजुर्ग दादी कर रही हैं। इस बेसहारा परिवार की मदद के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो लाख रुपये का चेक दिया है। क्षेत्रीय सपा कार्यकर्ताओं ने इस परिवार की कहानी अखिलेश यादव के सामने रखी थी। इसके बाद उन्होंने सपा के जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र उर्फ जग्गी प्रधान, भटीपुरा ग्राम प्रधान कंवरपाल सिंह, सौराज सिंह, मोहित गिरी गोविंदपुरी और सुनील शर्मा की एक टीम मेघराजपुर गांव भेजी। सपा विधायक शाहिद मंजूर ने बताया कि अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की मदद का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से भेजी गई दो लाख रुपये की आर्थिक मदद का चेक वृद्ध महिला को सौंपा गया। सपा विधायक सत्यवीर त्यागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव को जैसे ही इस परिवार के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आर्थिक मदद की। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव जग्गी प्रधान ने वृद्ध महिला को ढाढ़स बंधाया। सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर गुर्मी ने भविष्य में भी बच्चों की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।।

चौकी में दो युवकों को पीटने और आसपा के महानगर अध्यक्ष से अभद्रता का आरोप

मेरठ, एजेंसी। रोहटा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो युवकों के हाथ पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पुलिस कर्मियों पर पीटने के आरोप का मामला सामने आया है। वहीं, एक निरीक्षक पर नजरबंद करने के दौरान आसपा के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद अनस से अभद्रता का आरोप लगा है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडेय से मुलाकात के दौरान दोनों मामलों की जांच व कार्रवाई की मांग की। आसपा के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने बताया कि शुक्रवार को दो युवकों को रोहटा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। परिजनों ने उन्हें जानकारी दी है कि दोनों युवकों को पुलिस चौकी पर ले जाकर पीटा गया। उनका कहना है कि हाथ पर जाति सूचक शब्द लिखने पर उन्हें पीटा गया है। इसके अलावा लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद अनस ने भी प्रतिनिधि मंडल को जानकारी दी कि बृहस्पतिवार रात उन्हें नजरबंद करने के लिए उनके घर पुलिस पहुंची। मोहम्मद अनस मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। एक निरीक्षक ने उनसे इस दौरान अभद्रता की। आरोप कि निरीक्षक ने उन्हें बुलडोजर चलवाने की भी धमकी दी। डीएम-एसएसपी से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने इन दोनों मामलों की शिकायत की। इसके अलावा पुलिस नने फईम आदि कई और लोगों को नजरबंद किया। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि दो बाइक पर पांच लोग जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोका था। जाति सूचक शब्द लिखने पर पीटने का आरोप निराधार है।

एसआईटी जांच की आंच से बच रहे हैं चंपत राय

सब कुछ था हाथ में पर कहीं नहीं हस्ताक्षर

लखनऊ, एजेंसी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कमान पूरी तरह से चंपत राय के हाथों में थी। जैसा वह चाहते थे, वही होता था, लेकिन एसआईटी जांच में उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लिखापढ़ी में ऐसे किसी भी दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं मिले, जिससे प्रकरण में उनका नाम आ सके। ऐसे सभी कार्य डॉ. अनिल मिश्रा ही देखते थे। लिहाजा अनिल मिश्रा तो नप गए, लेकिन अब तक चंपत राय तक जांच की आंच नहीं पहुंची।

चढ़ावा चोरी मामला उजागर होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा सबसे अधिक सवालों के घेरे में थे। जब एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो उसमें अनिल मिश्रा का नाम था। सीधे तौर पर उनको दोषी बनाया गया। मगर कहीं पर भी चंपत राय का जिक्र नहीं किया गया। इसको लेकर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। उसकी वजह है कि चंपत राय ही मुख्य रूप से ट्रस्ट चला रहे थे। बाकी लोग उनके साथ काम करते थे। उनका नाम न होना सभी को चौंका दिया था।

सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने जांच के दौरान पाया कि भले ही चंपत राय की भूमिका ट्रस्ट में अहम हो, लेकिन इस प्रकरण में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जहां पर उनकी भूमिका सामने आ रही हो। वहीं, जो दस्तावेज मिले, उनमें अनिल मिश्रा का नाम सामने आया। गोपाल राव का भी नाम लिखापढ़ी में नहीं मिला, इसलिए एसआईटी ने सिर्फ अनिल मिश्रा को दोषी पाया। रिपोर्ट में उन्हीं का जिक्र है।

बचे चंपत और अनिल फंसे

बैंक से हुए एमओयू पर अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर थे। वहीं, गणना प्रक्रिया की जो एसओपी तय हुई थी, उसमें अनिल मिश्रा व बैंक अधिकारी थे। इसमें कहीं पर चंपत राय के हस्ताक्षर किसी कागज पर नहीं हुए। एसआईटी ने इन दस्तावेजों को साक्ष्यों के तौर पर जांच में शामिल किया। जिससे चंपत राय बच गए और अनिल फंस गए।

विस्तृत जांच में हो सकता है जिक्र

एसआईटी प्रकरण की प्रारंभिक जांच पूरी कर चुकी है। अगले पांच दिन में विस्तृत जांच भी पूरी हो जाएगी। 15 जुलाई को या फिर उसके बाद किसी भी दिन एसआईटी विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी की जांच जिस दिशा में चल रही है, उसके मुताबिक विस्तृत जांच में चंपत राय की भूमिका का जिक्र किया जा सकता है। इसमें उनको लापरवाही का दोषी बनाया जा सकता है।

क्योंकि प्रबंधन की निगरानी व देखरेख की जिम्मेदारी उनकी ही थी।

एक वजह ये भी...

अनिल मिश्रा और चंपत राय को लापरवाही का दोषी इसलिए भी बनाया जाएगा क्योंकि जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर कर्मियों की मंदिर में भर्ती की गई और उनको संवेदनशील चीजों की जिम्मेदारी दी गई। वह इन सभी पर सवाल खड़े करता है। वहीं, चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियों का होना सबसे बड़ा सुबूत है।

पुलिस की कार्रवाई से डरकर भाग रहे गणनाकर्मी

चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी और पुलिस की कार्रवाई से वहां के कर्मचारियों में डर और दहशत है। तमाम कर्मचारी काम पर आना ही बंद कर दिया है। वहीं गणना में लगे 20-25 कर्मी भी काफी समय से नहीं आ रहे हैं। अन्य कर्मियों की मदद से दान राशि की गणना की जा रही है। जो गणना कर्मी नहीं आ रहे हैं उनमें करीब दस ऐसे हैं, जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है। उनको आशंका है कि उनकी पर कहीं कार्रवाई न हो जाए। बैंक ने सैनिक सिक्योरिटी कंपनी के लिए 46 हाउसकीपिंग कर्मियों को रखा था। ये सभी गणना में लगाए गए थे। घटना में शामिल छह आरोपी अनुकल्प, लवकुश, मनीष, अविनाश, करुणेश और रमाशंकर चोरी में जेल भेजे गए थे। ये सभी 46 कर्मियों में ही शामिल थे।

कंपनी ने इनको निकाल दिया था। वहीं बाकी के कर्मचारी गणना में लगे हुए थे। करीब दस दिन पहले इसमें से एक-एक कर कर्मचारी काम पर आना बंद करते रहे। वर्तमान में सिर्फ 17-18 कर्मी ही आ रहे हैं। अन्य ने आना बंद कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक इनमें से अधिक कर्मियों से एसआईटी व पुलिस ने पूछताछ भी की थी। कुछ की भूमिका भी संदिग्ध है। इसी वजह से ये सभी वहां से कतराते रहे और अब पूरी तरह से काम पर आना बंद कर दिया है।

मंदिर से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि कर्मियों ने नौकरी ही छोड़ दी है। हालांकि मामले में कंपनी का कहना है कि अब तक वही छह कर्मी हटाए गए जो जेल गए हैं। बाकियों का कोई इस्तीफा आदि नहीं मिला है।

फर्जी दस्तावेज से वक्फ संपत्ति हड़पने के आरोपी की जमानत खारिज

वाराणसी, एजेंसी। दालमंडी रोड चौड़ीकरण योजना के दौरान अधिग्रहित की जा रही वक्फ संपत्ति के नामांतरण में कथित फर्जीवाड़े और कब्जे के प्रयास के मामले में आरोपी मो. आजम को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने उसकी पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष तिवारी ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन के अनुसार, मस्जिद नेसारन खां के मुतवल्ली शकील अहमद ने चौक थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि दालमंडी रोड चौड़ीकरण योजना के तहत अधिग्रहित हो रही वक्फ संपत्ति के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नगर निगम के अभिलेखों में गलत तरीके से नाम दर्ज कराया गया। अभियोजन का कहना है कि सह-आरोपी जहांगीर ने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, जबकि मो. आजम ने जावेद, अरशद और आलमगीर के साथ मिलकर इस कथित षड्यंत्र में सहयोग किया। आरोप यह भी है कि आरोपियों ने मस्जिद की पहली मंजिल पर बने करीब 1200 वर्गफीट के हॉल पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर मुतवल्ली को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मामला मूल रूप से संपत्ति विवाद से जुड़ा है। उनका कहना था कि मो. आजम का न तो कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कराने से कोई संबंध है और न ही धमकी देने की घटना से उनका कोई लेना-देना है। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नगर निगम में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने और नामांतरण कराने से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य विवेचना में सामने आए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर माना और मो. आजम की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी।

शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमाई को वैध बनाने का खेल

ईडी ने खंगाला पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह का नेटवर्क

लखनऊ, एजेंसी। सी की गरौठा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच अब उनके कारोबारी नेटवर्क तक पहुंच गई है। जांच में पता चला है कि पूर्व विधायक ने कथित तौर पर अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए शेल कंपनियों का जाल बिछाया था। इन कंपनियों में उनके तीन करीबी साझेदार निदेशक थे, जिनके जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया।

अब ईडी तीनों की भूमिका और उनकी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों से कई कंपनियों के बीच वित्तीय लेन-देन, तीसरे पक्ष के साथ हुए समझौते और संदिग्ध ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं।

जांच में कुछ ऐसी कंपनियां भी सामने आई हैं, जो केवल कागजों पर संचालित हो रही थीं। एजेंसी को आशंका है कि इन्हीं कंपनियों के जरिए कथित अपराध से अर्जित धन को वैध कारोबार का रूप देकर विभिन्न जगहों पर निवेश किया गया। ईडी को यह भी पता चला है कि कथित अवैध कमाई को अपने, परिजनों और करीबी सहयोगियों के नियंत्रण वाली कंपनियों में लगाया गया। इसके अलावा दूर के रिश्तेदारों के नाम पर भी कई चल और अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

पूछताछ के लिए तलब कर सकती : जांच एजेंसी अब इन निवेशों की पूरी श्रृंखला खंगाल रही है, ताकि धन के स्रोत और उसके अंतिम इस्तेमाल का पता लगाया जा सके। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ईडी तीनों निदेशकों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है।

यदि जांच में उनकी भूमिका की पुष्टि होती है तो उनकी संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। एजेंसी ने संदिग्ध बेनामी संपत्तियों और कथित अपराध से अर्जित धन को छिपाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले ही कब्जे में ले लिए हैं।

रिश्तेदारों के नाम खरीदीं संपत्तियां : ईडी की जांच में सामने आया है कि दीप नारायण सिंह ने दूर के रिश्तेदारों के नाम पर भी कई चल और अचल संपत्तियां खरीदीं। तलाशी के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनमें बेनामी निवेश और संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। एजेंसी अब इन संपत्तियों की वास्तविक फंडिंग और मालिकाना हक की पड़ताल कर रही है।

प्रदेश में बैंक ऋण वसूली में बड़ा सुधार

एक साल में 13.91 लाख आरसी और 19 हजार करोड़ की देनदारी घटी

लखनऊ, एजेंसी। पिछले एक साल में बैंक ऋण वसूली की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैंकों ने शासन को भेजी संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक लंबित रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) 23.23 लाख से घटकर 9.32 लाख रह गए, यानी 13.91 लाख की कमी आई।इनसे जुड़ी लंबित राशि भी 36,994 करोड़ रुपये से घटकर 17,856 करोड़ रुपये रह गई।

वहीं, सरफेसी अधिनियम के तहत लंबित आवेदन 4,953 से घटकर 4,497 रह गए। हालांकि रिपोर्ट में जिला स्तर पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और सरफेसी मामलों की निगरानी के लिए अलग पोर्टल विकसित करने की जरूरत भी बताई गई है।

बैंकों ने कहा है कि जिला स्तर पर संपत्ति का कब्जा दिलाने में देरी के कारण बैंकों की ऋण वसूली प्रभावित हो रही है। इस कारण बैंकों ने राजस्व विभाग और जिला प्रशासन से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने का अनुरोध किया है।

बैंकों ने वर्ष 2026 में सरफेसी मामलों की निगरानी के लिए अलग पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए राजस्व विभाग, गृह विभाग, एसएलबीसी और प्रमुख बैंकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर प्रारूप अंतिम रूप देने की बात कही गई है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि बैंकों द्वारा ऑनलाइन दर्ज आरसी के आंकड़ों और वास्तविक वसूली के मिलान के लिए राजस्व परिषद को पोर्टल अपडेट करने और स्थिति का समन्वय करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा सरफेसी मामलों में भौतिक कब्जा दिलाने की प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर दिया गया है।

456 मामलों का निस्तारण हुआ

स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की दिसंबर 2024 और मार्च 2026 की रिपोर्ट की तुलना करें तो बैंक ऋण वसूली में उल्लेखनीय सुधार सामने आया है। सरफेसी अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेटों के स्तर पर लंबित मामलों में भी मामूली सुधार हुआ है। दिसंबर 2024 में ऐसे 4,953 आवेदन लंबित थे, जो मार्च 2026 तक घटकर 4,497 रह गए। यानी 456 मामलों का निस्तारण हुआ।

नगर निगम कार्यकारिणी समिति के छह नए सदस्यों के लिए 16 को चुनाव, सरगर्मियां तेज

गोरखपुर, एजेंसी। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम सदन की 21वीं बैठक 16 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे नवनिर्मित सदन हाल में होगी, जिसमें कार्यकारिणी समिति के छह सदस्यों का निर्वाचन कराया जाएगा। नगर आयुक्त अजय जैन ने मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव के निर्देश पर पदेन सदस्यों, निर्वाचित पार्षदों और नामित पार्षदों को बैठक की सूचना जारी कर दी गयी है।

बैठक में 26 मई और तीन जुलाई को हुई सदन की बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि के साथ कार्यकारिणी समिति के छह नए सदस्यों का निर्वाचन होगा। मेयर की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। वर्तमान कार्यकारिणी के उपसभापति पवन कुमार त्रिपाठी समेत भाजपा के पांच सदस्य और सपा के रमेश यादव का कार्यकाल पूरा होने के कारण वे स्वतः बाहर हो जाएंगे। पवन त्रिपाठी का उपसभापति पद भी उसी दिन समाप्त हो जाएगा। नए उपसभापति का चुनाव बाद में नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक में कराया जाएगा।

नगर निगम सदन में भाजपा के बहुमत को देखते हुए उसके पांच और समाजवादी पार्टी के एक सदस्य का कार्यकारिणी में चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सपा शुक्रवार को बैठक कर अपने उम्मीदवार के नाम पर निर्णय लेगी, जबकि भाजपा भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करेगी। यदि सभी नामों पर सहमति बन गई तो छह सदस्यों का निर्वाचन सर्वसम्मति से हो जाएगा। वहीं उपसभापति पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

27 सेकंड में 8 बार सड़क पर पटका, दरिंदे के हाथ भी न कांपे, कोर्ट ने सुनाई फांसी

फिरोजाबाद, एजेंसी। शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में डेढ़ साल के आरव की निर्मम हत्या के दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को जिला जज की अदालत ने फांसी और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीसीटीवी फुटेज और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना।

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई 2026 की दोपहर डेढ़ साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी बदायूं को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के 41वें दिन जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से इस सजा का एलान हुआ।

दोषी अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, सिविल लाइंस, बदायूं को अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में पुलिस दोषी विराज को जेल से अदालत लेकर पहुंची। दोपहर

पौने तीन बजे करीब अदालत ने सजा का एलान किया तो विराज फूट-फूटकर रोने लगा। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहियां पूरी तरह पुख्ता हैं।

विराज ने मायके और ससुराल की अनबन का उठाया था फायदा: मूल रूप से अरांव के गांव बामई निवासी रति शर्मा की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के कारण रति जनवरी 2026 से अपने मायके में रह रही थी। 30 मई को पति पर कानूनी कार्रवाई की सलाह लेने के लिए शिकोहाबाद में एक अधिवक्ता से मिलने अपनी मां पिंकी देवी के साथ गई थी। अधिवक्ता ने पांच बजे मिलने का समय दिया था, तो वह मां के साथ अपनी मुंह बोली मौसी के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी स्थित घर चली गई थी।

वहां सुमित का फुफेरा भाई विराज उर्फ जितेंद्र पाठक आ गया और रति को अपनी बातों में फंसाने लगा। विराज ने रति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रति ने ठुकरा दिया था। शादी से इन्कार पर बौखलाए विराज ने खौफनाक साजिश रची। डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ बाहर ले गया। घर से महज 50 मीटर दूर सुनसान सड़क पर ले जाकर दरिंदे ने रति से अपना बदला लेने के लिए मासूम आरव को 27 सेकंड के भीतर लगातार 8 बार पक्की सड़क पर बेरहमी से पटक-पटककर मार डाला।

मुठभेड़ में हुई थी गिरफ्तारी

रूह कंपा देने वाली यह वारदात सड़क पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जो कोर्ट में सबसे बड़ा और साक्ष्य साबित हुआ। वारदात के बाद आरोपी बच्चे के शव को घर के दरवाजे पर फेंककर भाग गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ ही घंटों बाद रात में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ के दौरान पैर में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हुआ था।

आरव को रास्ते का रोड़ा समझता था

दोषी विराज के दिमाग में एक सनक सवार हो चुकी थी। उसे लगता था कि रति उससे शादी सिर्फ अपने डेढ़ साल के बेटे आरव की वजह से नहीं करना चाहती है। रति को हमेशा के लिए अपना बनाने की इसी सनक में विराज ने मासूम आरव को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

जघन्य अपराध की मिली सजा

फिरोजाबाद, एजेंसी। डेढ़ साल के आरव की पटककर हत्या करने वाले अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को शुक्रवार को फिरोजाबाद के जिला जज की कोर्ट से फांसी की सजा हुई है। जब यह सूचना अभियुक्त के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शेखपुर स्थित घर में रहने वाले भाइयों को मिली तो सन्नाटा छा गया। मां गुमसुम हो गईं। कुछ लोग घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। विराज के बड़े भाई ने कहा, उसने जो जघन्य अपराध किया, उसे उसकी सजा मिली है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक के पिता विशेंद्र पाठक का पहले ही निधन हो चुका है। वह मंदिर के पुजारी थे। सभी भाई पिता के पैतृक कार्य पूजा-पाठ और शादी-विवाह करने का काम करते हैं। अभियुक्त चार भाइयों में सबसे छोटा है। विराज को फांसी की सजा होने के बाद उसके बड़े भाई मुनीश पाठक ने बताया कि उसने जो जघन्य अपराध किया, उसे उसकी सजा मिली। मुनीश ने बताया कि विराज का दिमागी संतुलन सही नहीं था, जिसका इलाज चल रहा था। वह नशे का भी आदी हो गया था। वर्ष 2018 में दो मंजिल से गिरने के बाद उसका दिमागी संतुलन और बिगड़ गया था। वह छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करने लगा था। उसका 15-15 दिन में स्वभाव बदल जाता था। इसी स्वभाव के कारण एक बार मुझे भी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। बात-बात कर गुस्सा करने की वजह से उसकी शादी नहीं कराई, जबकि रिश्ते कई आए थे। बरेली से काफी लंबा इलाज चला, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।बड़े भाई मुनीश ने बताया कि फैसले के बारे में बीमार मां को पूरी जानकारी नहीं दी है। अभी ये जानकारी देंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। मां से मिलने की बात पर तीनों भाइयों ने साफतौर पर इन्कार कर दिया। बातचीत के दौरान मां घर से निकलकर गेट तक आईं।

चिंताहरण महादेव मंदिर परिसर में एचपीसीएल टीम का स्वच्छता अभियान

मथुरा। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रेवाड़ी-कानपुर पाइपलाइंस टीम द्वारा ब्रज क्षेत्र में 'स्वच्छता पखवाड़ा' के अंतर्गत व्यापक स्तर पर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुरानी गोकुल-महावन स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान वरिष्ठ प्रबंधक टीएम शिवकुमार के नेतृत्व में 01 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया जा रहा है। इसके तहत टीम द्वारा ब्रज क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान केवल सफाई कार्य ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच पौधों का वितरण भी किया गया। टीम के अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण समाज की आधारशिला हैं और ब्रज क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ व हरित बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। अधिकारियों के अनुसार 'स्वच्छता पखवाड़ा' के तहत ब्रज के विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान टीम के सदस्य अमित कुमार, आयुष्मान, पंत, अर्पित, राहुल, आनंद, प्रदीप शर्मा, राजेन्द्र और जितेश सहित अन्य सदस्यों ने श्रमदान कर मंदिर परिसर की सफाई में सक्रिय योगदान दिया। स्थानीय नागरिकों और मंदिर के मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह तरकर ने इस पहल की सराहना की।

बरसाना नगर पंचायत लगाएगी तीन हजार वृक्ष

बरसाना। प्रदेश सरकार द्वारा राज्यव्यापी वृक्षारोपण महाअभियान (वन महोत्सव) की पूर्व संध्या पर बरसाना नगर पंचायत द्वारा गहवर वन परिक्रमा मार्ग स्थित चिकसोली मुक्तिधाम में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व जेल विजिटर लक्ष्मण प्रसाद शर्मा और नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी डॉ. कल्पना वाजपेयी ने एक-एक कदम्ब किया। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में कदंब वाटिका विकसित की जाएगी। तीन हजार पौधे रोपकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरित संकल्प को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान के तहत लगाए जाने वाले पेड़ों की रक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। पेड़ों की देखभाल एवं समय समय पर पेड़ों में पानी देने के लिए प्रत्येक नगर पंचायत कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्य अतिथि पूर्व जेल विजिटर लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने कहा कि वृक्ष हमारी धरोहर है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हरी भरी धरोहर को बचाए रखना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। नगर क्षेत्र में इस मौके पर चिकसौली के सभासद विश्वेंद्र जादौन,नगर पंचायत के बड़े बाबू अमित कुमार, रवि शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी गौरव शर्मा, गोला पेंटर आदि मौजूद रहे।

हत्या के प्रयास में वांछित पिता पुत्र राल से गिरफ्तार

चौमुहां। थाना जैंत पुलिस ने ग्राम राल में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास (जानलेवा हमले) के मुकदमे में वांछित चल रहे दो मुख्य आरोपियों पिता-पुत्र को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार 10 जुलाई रात करीब 10.05 बजे जैंत थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुधीर राठी, उपनिरीक्षक संदीप कुमार, रामदेव शर्मा और महिला उपनिरीक्षक काजल भारद्वाज की संयुक्त पुलिस टीम ने ग्राम थोक भोज (राल) में दबिश दी। पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए घर से आरोपी लोकमन (70 वर्ष) पुत्र रामजीलाल और उसके बेटे प्रताप (40 वर्ष) को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ जैंत थाने में धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109 और 352 बीएनएस के तहत जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल यतेन्द्र सिंह, कांस्टेबल रंजीत कुमार, सत्येंद्र कुमार और रिक्रूट कांस्टेबल कुलभूषण शामिल रहे। पुलिस घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों और लाइसेंसी रायफल की बरामदगी के लिए दबिश दे रही है।

स्कूलों में सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट के गुर सिखाएंगे विशेषज्ञ

डिजास्टर एक्सपर्ट्स की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हरदयाल कॉलेज में हुआ।

फरह। प्रदेश के 1.40 लाख विद्यालयों में सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट के गुर सिखाएंगे विशेषज्ञ। इन डिजास्टर विशेषज्ञों के लिए फरह स्थित हरदयाल टेक्निकल कॉलेज में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। विद्यालयों को सुरक्षित एवं आपदा-प्रतिरोधी बनाने के उद्देश्य से संचालित स्कूल सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों का सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। डिजास्टर एक्सपर्ट्स बनाने का कार्य चयनित संस्था बेनेट कोलमैन लिमिटेड द्वारा होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत सीनियर मैनेजर (डिजास्टर) मनोज कुमार सिंह के साथ प्रबंधन टीम के मुख्य सदस्य दीपक गुप्ता, पंकज मिश्रा और देवेन्द्र सिंह विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करेंगे। परियोजना प्रबंधन टीम ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को अधिक सुरक्षित, आपदा-सक्षम बनाना और विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित व संरक्षित शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। तीन दिनों तक चलने वाले इस आवासीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को स्कूल सेफ्टी ऑडिट की कार्यप्रणाली तथा स्ट्रक्चरल एवं नॉन-स्ट्रक्चरल सुरक्षा मूल्यांकन, फायर एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के आधारभूत सिद्धांत, आपदा जोखिमों की पहचान और आकस्मिक सुरक्षा उपाय, मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल डेटा संग्रह, रिपोर्टिंग तथा साक्ष्य अपलोड करने की आधुनिक प्रक्रिया आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरांत फील्ड ऑडिटर्स, डिजास्टर एक्सपर्ट्स, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स तथा सिविल इंजीनियर्स की एक संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा। यह प्रशिक्षित टीम प्रदेश भर के विद्यालयों में जाकर धरातल पर सुरक्षा और जोखिम आकलन का कार्य करेगी, ताकि परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। यह उत्तर प्रदेश के शैक्षिक ढांचे को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर लिया संज्ञान

कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में दो युवकों को किया गिरफ्तार

मथुरा। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने साइबर फ्रॉड करने वाले दो युवकों को दो मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड व 7000 रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भूतेश्वर अखाड़े वाली गली में पोखर के पास से यश राठौर पुत्र शिवशंकर, निवासी नई पानी की टंकी के पास कृष्णा विहार, थाना कोतवाली जनपद मथुरा व.सनी सिसोदिया पुत्र सतीश सिसोदिया निवासी जी ब्लॉक जनकपुरी मोहाली रोड थाना कोतवाली जनपद मथुरा गिरफ्तार किया। एनसीआरपी पोर्टल के मुताबिक विभिन्न राज्यों से तीन साइबर शिकायतें इनके खिलाफ दर्ज की गई है।कार्यवाही करने वाली टीम में निरीक्षक अपराध सुनील कुमार थाना कोतवाली, एसआई मुश्ताक मेहदी (साइबर हेल्प डेस्क नोडल प्रभारी थाना कोतवाली मथुरा) आदि थे।

स्वच्छ ब्रज महाअभियान में अब संत समाज की होगी भागीदारी

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर श्रद्धालुओं को दिलाया जाएगा स्वच्छता का संकल्प

मथुरा। ब्रज केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और विश्व की आध्यात्मिक चेतना का जीवंत केंद्र है। श्रीमद्भागवत, पुराणों और संत साहित्य में वर्णित ब्रज की पावन भूमि सदियों से भक्ति, प्रेम, करुणा और लोकमंगल का संदेश देती आई है। ऐसे दिव्य धाम की स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से संचालित श्हम सबने यह ठाना है, ब्रज को स्वच्छ बनाना हैश् महाअभियान में अब संत समाज, गुरुजन और भागवताचार्यों की सक्रिय भागीदारी होने जा रही है। वे ब्रज दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाएंगे तथा ब्रज को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की जन्म एवं लीलास्थली ब्रज में प्रतिवर्ष करीब 10 करोड़ श्रद्धालु दर्शन को आते हैँ। यहाँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, राधाकुंड सहित ब्रज के अन्य प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में अनेक संतों, महंतों और भागवताचार्यों के आश्रम स्थित हैं। जहां श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन के साथ इन आश्रमों में सत्संग, भागवत कथा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। इसी व्यापक आध्यात्मिक प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद अब संत समाज को स्वच्छता अभियान से जोड़ते हुए इन्हें महत्वपूर्ण सहभागी बनाने जा रहा है। यह गुरु महाराज और भागवताचार्य अपने प्रवचनों, सत्संगों और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को यह संकल्प दिलाएंगे कि वे ब्रज में कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाएंगे, एकल-उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे तथा यमुना तट, कुंडों, घाटों, परिक्रमा मार्गों और सभी धार्मिक स्थलों की स्वच्छता एवं पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करेंगे। श्रद्धालुओं को यह भी बताया जाएगा कि ब्रज की स्वच्छता केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण की सेवा, ब्रज रज का सम्मान और अपनी आस्था के प्रति कर्तव्य है। ब्रज की पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक भक्त की धार्मिक जिम्मेदारी भी है। उल्लेखनीय है कि हम सबने यह ठाना है, ब्रज को स्वच्छ बनाना है महाअभियान उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप देना तथा ब्रज की आध्यात्मिक गरिमा, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। ब्रज की पहचान केवल मंदिरों, कुंडों और परिक्रमा मार्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक पवित्रता और सांस्कृतिक चेतना से भी है। ब्रज को स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। संत समाज, गुरु महाराज और भागवताचार्यों का समाज पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव है। उनके माध्यम से यदि स्वच्छता का संदेश प्रत्येक श्रद्धालु तक पहुंचेगा, तो यह अभियान जन आंदोलन का स्वरूप और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करेगा। ब्रज दर्शन के लिए आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यह संकल्प लेकर जाए कि वह स्वयं भी स्वच्छता का पालन करेगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। ब्रज में गंदगी फैलाना केवल पर्यावरण के प्रति लापरवाही नहीं, बल्कि इस पावन धाम की गरिमा और हमारी आस्था के प्रति भी अनुचित आचरण है।

ई रिक्शा चालकों ने तीन दिन की हड़ताल का किया ऐलान

- लगातार चालान और सीज करने की कार्यवाही का कर रहे हैं विरोध
- मथुरा-वृंदावन में 12 से 14 जुलाई तक 27 हजार ड्राइवर काम नहीं करेंगे

मथुरा। शनिवार को मथुरा वृंदावन में संचालित ई रिक्शा चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। प्रस्तावित हड़ताल 12, 13 और 14 जुलाई को होगी। अगर आप 12, 13 या 14 जुलाई को मथुरा वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन तीन दिनों के दौरान श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ई रिक्शा चालकों के बीच पूर्ण सहमति बन पाना आसान नहीं है। ऐसे में हड़ताल का आंशिक असर भी देखने को मिल सकता है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो निर्धारित तीन दिनों तक मथुरा-वृंदावन में ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। फिलहाल, इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ई रिक्शा समिति के सदस्य राजकुमार कुशवाह ने बताया कि मथुरा वृंदावन में करीब 27 हजार ई-रिक्शा चालक पिछले चार महीनों से लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से चालकों पर 20-20 हजार रुपए तक के भारी चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ई रिक्शा वाहनों को सीज किया जा रहा है और रूट प्रक्रिया के नाम पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यदि हड़ताल होती है, तो हजारों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनियन का आरोप है कि पिछले चार महीनों से पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा चालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। छोटी-छोटी बातों पर 20-20 हजार रुपये तक के भारी चालान किए जा रहे हैं और वाहनों को सीज किया जा रहा है। राजकुमार कुशवाहा ने यह भी बताया कि रूट नंबर आवंटित करने के नाम पर चालकों से 3 हजार रुपये लिए गए थे। इसके बावजूद न तो कोई स्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई और न ही अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूट प्रणाली चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गई है और इसके नाम पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऑटो यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि रूट सिस्टम को पूरी तरह समाप्त किया जाए। इसके साथ ही, भारी चालान और वाहन सीज करने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा चालकों के लिए उचित पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उप्र कर अधिवक्ता संगठन का धूमधाम से मनाया 11वा स्थापना दिवस

मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन डेम्पियर नगर में आयोजित किया कार्यक्रम

मथुरा। मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन (पंजी) मथुरा द्वारा उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन (पंजीकृत) लखनऊ का 11वा स्थापना दिवस डैंपियर नगर स्थित होटल हीरा कुंज रेसीडेंसी में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा संयुक्त रूप से केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट हरे कृष्ण अग्रवाल ने संगठन के द्वारा अधिवक्ता हित में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह संगठन कानूनी क्षेत्र, विशेष रूप से कर कानून में काम करता है। यह प्रदेश के कर अधिवक्ताओं को संगठित करके एक मजबूत मंच प्रदान करता है एवं हर माह अधिवक्ताओं के ज्ञानवर्धन के लिए जी एस टी एवं आयकर के वेबिनार सेमिनार आयोजित करता है और निरन्तर जारी है। उपकास की स्थापना 11 जुलाई 2015 में हुई थी। इस संस्था का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह भगवान योगीराज श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हुआ। आगरा से आई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य प्रत्याशी एडवोकेट हरजीत अरोड़ा ने कहा स्थानीय बार को कोई समस्या आती है तो वह उन समस्याओं को संगठन के माध्यम से बार काउंसिल व सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान करा सकते हैं। संगठन में ही शक्ति हैं। मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नीरज कुमार गर्ग ने भी संगठन की स्थापना से अब तक के कार्यों से अवगत कराया और संगठन के द्वारा अधिवक्ता हित में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम को अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन के महामंत्री एड. रामा कांत भारद्वाज ने किया एवं कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन सहभोज के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नीरज कुमार गर्ग, रमा कांत भारद्वाज, कोषाध्यक्ष बृजमोहन, राजीव पाराशर, रितेश माहेश्वरी, गौरव गर्ग, लक्ष्य अग्रवाल, मीडिया प्रभारी शुभम अग्रवाल, हीरेंद्र कुमार शर्मा, हर्षवर्धन मंगल, हरे कृष्ण अग्रवाल, अम्बरीश खंडेलवाल, गिरीश कुमार अग्रवाल, वेद प्रकाश गोस्वामी, सौरभ अग्रवाल, आशीष गर्ग, पवन कुमार अग्रवाल, उपेन्द्र चतुर्वेदी, महेश वर्मा, सौरभ कुमार अग्रवाल, सन्तोष अग्रवाल, माधव खंडेलवाल, राजन सिंह राजपूत, निखिल गोस्वामी, राधे कृष्ण अग्रवाल, आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

राया में बरेली हाईवे पर भैंसों से भरा कैंटर पलटा

टायर फटने से हुआ हादसा; पशु क्रूरता अधिनियम पर उठे सवाल

मथुरा। थाना राया क्षेत्र में शनिवार को मथुरा-बरेली हाईवे पर भैंसों से भरा एक कैंटर टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसा गांव वृंदावन की नगरिया के पास रेलवे पुल से उतरते समय हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से भैंसों को सुरक्षित बाहर निकालकर चालक के सुपुर्द कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कैंटर तेज गति से जा रहा था। रेलवे पुल से उतरते ही अचानक उसका टायर फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कैंटर पलट गया। हादसे में कुछ भैंसें घायल हो गईं, जबकि कई भैंसें सड़क किनारे इधर-उधर भागने लगीं। कैंटर चालक कमल ने बताया कि वह महावन पशु पेंठ से 15 भैंसें लेकर अलीगढ़ जा रहा था। रास्ते में अचानक टायर फटने से यह दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना पर उपनिरीक्षक रविंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

शातिर बदमाश भूरा के दौनों पैरों में लगी गोली, गिरफ्तार

- अपहरण और लूट का शातिर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
- पुलिस से मुठभेड़ में शातिर के दोनों पैरों में लगी गोली

मथुरा। अपहरण के प्रयास को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई सफेद कार का राज पुलिस ने खोल दिया है। करीब पांच स्थानों पर कार द्वारा लगातार अपहरण के प्रयास की खबरें मिल पुलिस को बेचैन कर रही थीं। कार तक पहुंचने और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया था। जनपद के बलदेव क्षेत्र में पुलिस, स्वाट टीम और महावन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अपहरण और लूट के आरोपी ओमप्रकाश उर्फ भूरा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे के हथौड़ा अंडरपास के समीप चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओमप्रकाश उर्फ भूरा (35)पुत्र राधारमण, निवासी जुलेंडी, थाना गोवर्धन ,हाल निवासी नगला साखी, हरिकृपा धाम कॉलोनी, गोवर्धन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है। सीओ संजीव कुमार राय ने बताया आरोपी के खिलाफ बलदेव, महावन, गोवर्धन व कोतवाली थानों में अपहरण, लूट, छेड़छाड़, मारपीट, बलवा, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में 9 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके अन्य आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। आवश्यक सख्त कार्रवाई होगी।

मुठभेड़ के दौरान हत्या के आरोपी को लगी गोली

गोविन्द नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है हत्यारोपी दीपक

मथुरा। नगर में गोविन्दनगर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर दीपक को शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सिटी आईपीएस आशना चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम चक्रतीर्थ घाट के पीछे गऊघाट की ओर कच्चे रास्ते पर आरोपी की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल से जा रहे दीपक को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार दीपक गोविन्दनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके विरुद्ध हत्या, गैंगस्टर अधिनियम, मादक पदार्थ संबंधी कानून और शस्त्र अधिनियम सहित 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह हाल में हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी के पास से बिना नंबर प्लेट की सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल, .315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस तथा दो खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुस्तकालय ज्ञान का शोध एवं उपचार का केंद्र है: रेखा रानी

मथुरा। नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन परिसर में संस्थान के सचिव प्रवीण गुप्ता, निदेशक डॉ राजीव द्विवेदी ने शुभारंभ किया। संस्थान के निदेशक ने कहा पुस्तक केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण नैतिक मूल्यों के विकास तथा सकारात्मक सोच की आधारशिला भी है। मोबाइल लाइब्रेरी जैसी अभिनव योजना विद्यार्थियों शोधार्थियों में पढ़ने की जागरूकता फैलती है। शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाती हैं। संस्थान से शोध एवं प्रकाशन सहायक डॉ करुणेश उपाध्याय ने बताया मोबाइल लाइब्रेरी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्र के अधीन कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट के अंतर्गत विद्यार्थी को समर्पित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं तथा उत्कर्ष एवं बहू विषय एक पुस्तकों को उपलब्ध कराना तथा समाज में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह एक चलती फिरती लाइब्रेरी है इसे अवसर पर पुस्तकालय सहायक श्रीमती रेखा रानी ने नेशनल बुक ट्रस्ट की टीम का स्वागत करते हुए पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान का शोध एवं उपचार का केंद्र है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस अवसर पर लाभ उठाने तथा नियमित रूप से पुस्तकों से अध्ययन एवं प्रेरणा लेने का आग्रह किया। इसे अवसर पर संस्थान के प्रशासन अधिकारी रजत शुक्ला, करवेंद्र सिंह, बृजेश कुमार, हेमंत कुमार आदि संस्थान कर्मी उपस्थित रहे।संस्थान के निदेशक ने कहा पुस्तक केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण नैतिक मूल्यों के विकास तथा सकारात्मक सोच की आधारशिला भी है मोबाइल लाइब्रेरी जैसी अभिनव योजना विद्यार्थियों शोधार्थियों में पढ़ने की जागरूकता फैलती है शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाती हैं। संस्थान से शोध एवं प्रकाशन सहायक डॉ करुणेश उपाध्याय ने बताया मोबाइल लाइब्रेरी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्र के अधीन कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट के अंतर्गत विद्यार्थी को समर्पित है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं छात्र-छात्राओं तथा उत्कर्ष एवं बहू विषय एक पुस्तकों को उपलब्ध कराना तथा समाज में पठन-पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देना है यह एक चलती फिरती लाइब्रेरी है इसे अवसर पर पुस्तकालय सहायक श्रीमती रेखा रानी ने नेशनल बुक ट्रस्ट की टीम का स्वागत करते हुए पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान का शोध एवं उपचार का केंद्र है उन्होंने विद्यार्थियों से इस अवसर पर लाभ उठाने तथा नियमित रूप से पुस्तकों से अध्ययन एवं प्रेरणा लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रशासन अधिकारी रजत शुक्ला, करवेंद्र सिंह, बृजेश कुमार, हेमंत कुमार आदि संस्थान कर्मी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय हनुमान दल की बैठक में संगठन मजबूती पर जोर

मथुरा। राष्ट्रीय हनुमान दल की एक बैठक गणेश बाग माता मनकामेश्वरी देवी मंदिर परिसर पर आयोजित की गयी। जिसमें संगठन की आगामी गतिविधियों संगठन विस्तार सदस्यता अभियान व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ नरेंद्र रावत ने कहा कि हनुमान दल अखंड राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र निर्माण जनसंख्या नियंत्रण गौरक्षा धर्म रक्षा नारी रक्षा राष्ट्र रक्षा अखंड हिन्दू राष्ट्र और मानव सेवा के लिये समर्पित है। ब्रज क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विशाल पाराशर ने संगठन मजबूती और हिन्दू समाज को एकजुट करने को लेकर सदस्यता अभियान चलाकर युवाओं को संगठन में जोड़कर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओ की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में ब्रज प्रदेश अध्यक्ष हाथरस मुकेश सारस्वत जिलाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी युवा जिलाध्यक्ष चन्द्रशेखर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अबसर पर मनोज नागर कुलदीप शास्त्री हरिओम चौधरी कुलदीप सिंह टीकाराम शर्मा भोलेशंकर शर्मा सुमित चौधरी अशोक चौधरी प्रमोद कुमार अतर सिंह शिवशंकर रामविहारी राजकुमार जितेंद्र नन्दकिशोर आदि संगठन के लोग मौजूद रहे।

कारोबारियों के साथ मिलकर चाइनीज मांझे प्रभावी नियंत्रण की तैयार की रणनीति

जीएसटी विभाग ने व्यापारियों के साथ आयोजित की समन्वय बैठक

मथुरा। घातक चाइनीच मांझे और लेड के लेप वाली डोरी की बिक्री, निर्माण आदि पर प्रभावी रोक के लिए जीएसटी विभाग ने कारोबारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर आपसी समन्वय से इन घातक माझे पर प्रभावी प्रतिबंध के लिए रणनीति तैयार की। ज्ञात रहे कि न्यायालय के आदेश के बाद भी इन घातक और जानलेवा माझे और डोरी पर प्रशासन प्रभारी नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने में अभी तक नाकाम रहा है। 11 जुलाई को राज्य कर कार्यालय गोवर्धन रोड मथुरा में चाइनीज मांझा, सिन्थेटिक मांझा, शीशा लेपित डोरी के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग को प्रभावी रूप से रोके जाने के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें धागा व्यापारी बन्धुओं एवं विभिन्न व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं राज्य कर विभाग मथुरा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा, शीशा लेपित डोरी के निर्माण, उपयोग व विक्रय को हतोत्साहित करने, रोक लगाने पर विचार विमर्श किया गया तथा उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-13864/2018, मोतीलाल यादव बनाम प्रधानमंत्री कार्यालय व अन्य तथा सम्बद्ध जनहित याचिका संख्या-499/2025, रज्जन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश 11 फरवरी 2026 के अनुपालन के क्रम में व्यापार मण्डल तथा सम्बन्धित व्यापारियों को चाइनीज मांझे पर प्रभावी रूप से रोक लगाये जाने के लिए जागरूक किया गया। उपस्थित व्यापारी बन्धुओं एवं व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के द्वारा न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया।

सडक हादसे में पिता की मौत, पत्नी बेटा गंभीर घायल

खाटू श्याम दर्शन कर लौटी पत्नी और बेटे को घर लेकर लौट रहे थे वीरेन्द्र

मथुरा। खाटू श्याम दर्शन कर लौटी पत्नी और बेटे को घर लेकर लौट रहे वीरेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई जबकि पत्नी और बेटा गंभीररूप से घायल हैं। तीनों एक बाइक पर सवार थे और गांव पहुंचने से ठीक पहले मौत ने झपट्टा मार दिया। थानाध्यक्ष कर्मवीर सिंह ने बताया कि गांव मल्हे के समीप जयपुर-बरेली हाईवे पर हुए इस एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। मृतक वीरेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है, प्रार्थना पत्र मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर बरेली हाईवे पर गांव मल्हे के समीप शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। कटैला निवासी वीरेंद्र सिंह (47) अपनी पत्नी सुनीता देवी और बेटे पंकज सिंह को रेलवे जंक्शन से बाइक पर लेकर गांव वापस आ रहे थे। मां और बेटा खाटू श्याम के दर्शन कर लौटे थे। सुबह लगभग 5 बजे जब वे बरेली हाईवे पर मल्हे गांव के पास पहुंचे और गांव की सड़क पर उतर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने बैंटनी, शिमला में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया

डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच मजबूत सेतु बनेगाः मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला के बैंटनी में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया। यह संग्रहालय आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित करने और दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंटनी का शिमला के इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यहां डिजिटल संग्रहालय की शुरूआत राज्य की विरासत के संरक्षण, सम्मान और वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नए संस्थान का उद्घाटन नहीं है, बल्कि विरासत संरक्षण के एक नए युग की शुरूआत है। यह डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। यहां आने वाले लोग हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए और रोचक तरीके से अनुभव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय को इस तरह तैयार किया गया है कि हर आयु वर्ग के लोग इतिहास को आसानी से समझ सकें और उससे जुड़ सकें। इसके लिए हाई-रेजोल्यूशन 3डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव टाइमलाइन और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन सुविधाओं के माध्यम से आगंतुक हिमाचल की लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक गाथाओं को जीवंत और आकर्षक रूप में देख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि संग्रहालय में शिमला के विकास की पूरी कहानी को दर्शाया गया है। इसमें एक छोटे से पहाड़ी नगर से ऐतिहासिक महत्व वाले शहर बनने तक की यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, महान विभूतियों के जीवन और योगदान, कालका-शिमला रेलवे, राज्य गठन के बाद की विकास यात्रा, समृद्ध कला एवं संस्कृति तथा पारंपरिक खान-पान को भी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह डिजिटल संग्रहालय भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य की अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसे वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाएगा। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक रीमा कश्यप और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

13 से 18 जुलाई तक धर्मशाला उपमंडल के तहत विद्युत शॅटडाउन का शेड्यूल जारी

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, विद्युत उपमंडल-2 धर्मशाला के सहायक अभियंता रमन भरमौरीया ने ने सूचित किया है कि विद्युत लाइनों के आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते 13 जुलाई से 18 जुलाई, 2026 तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 जुलाई को सकोह बाजार क्षेत्र में, 14 जुलाई को लोअर सकोह तथा पुलिस लाइन रोड क्षेत्र में, 15 जुलाई को रेडियो कॉलोनी, अपर सकोह एवं सुभाष नगर में, 16 जुलाई को चेलियां, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में, 17 जुलाई को नई कॉलोनी चेलियां में तथा 18 जुलाई को गुलेर मोहल्ला एवं बलौरिया मोहल्ला में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

बारा कोठा अंखन खोला-सुधेड़ सड़क 31 जुलाई तक रहेगी यातायात के लिए बंद

धर्मशाला, जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बारा कोठा अंखन खोला-सुधेड़ सड़क पर स्लैब कलवर्ट निर्माण कार्य के दृष्टिगत इस मार्ग को 10 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

इस अवधि में वाहनों का आवागमन एनएच-503 (धर्मशाला बाईपास रोड) के वैकल्पिक मार्ग से किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसी को कार्यस्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक एवं अन्य सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एंबुलेंस, अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें तथा यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके।

उपायुक्त ने भारी वर्षा के दृष्टिगत दिए अधिकारियों को निर्देश

सोलन। उपायुक्त सोलन एवं ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने भारी वर्षा के दृष्टिगत समस्त उपमण्डलाधिकारियों व अन्य सम्बन्धित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।

मनमोहन शर्मा ने ज़िला के सभी उपमण्डल, तहसील व दूर-दराज की उप तहसील में मानसून के दृष्टिगत 24ङ्ग7 कंट्रोल रूम स्थापित करने व आपातकालीन स्थिति में निरंतर निरीक्षण, समन्वय व त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैयार रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी, नालों व अन्य जल निकायों के पास बसी आबादी वाले क्षेत्रों का स्वयं जाकर निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित बनाएं कि किसी भी श्रमिक आवास व अन्य स्थाई मकान नदी, नालों व अन्य जल निकायों के पास न बना हो। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आपातकालीन स्थिति में निकालने की तैयारी भी करना सुनिश्चित बनाएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए नदी, नालों, जल निकायों, बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों, भूस्खलन सम्भावित स्थलों व अन्य आपदा सम्भावित क्षेत्रों पर उचित बैरिकेड, सूचना-पट्ट व सतर्कता सूचना पट्ट लगाना सुनिश्चित बनाएं।

उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी भारी वर्षा के दृष्टिगत स्थानीय निवासियों, दुकानदारों व पर्यटकों को समय पर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों को नदी के किनारे, पुलों और अन्य संवेदनशील जलमग्न क्षेत्रों के पास न जाने के निर्देश देने को कहा।

मनमोहन शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम चेतावनी, सुरक्षा सलाहकारी व आपातकालीन आदेशों को आमजन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करें ताकि लोगों तक शीघ्र सही जानकारी पहुंचाई जा सके। उपायुक्त ने इस दौरान निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों व सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ समन्वयन स्थापित करने के निर्देश दिए। मनमोहन शर्मा ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग व अन्य मार्गों में सिंगकिंग जोन, भूस्खलन सम्भावित क्षेत्र, क्षतिग्रस्त मार्ग व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर क्षतिग्रस्त व आपदा सम्भावित स्थलों पर उचित बैरिकेड व सतर्कता सूचना पट्ट लगाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने मानसून सीजन के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अनावश्यक स्टेशन लीव पर न जाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध रहे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि आपदा सम्भावित व संवेदनशील क्षेत्रों में भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन, अवरुद्ध सड़कें, अधोसंरचना नुकसान व अन्य किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना ज़िला आपातकालीन संचालन केन्द्र सोलन में देना सुनिश्चित करें।

इस वर्ष के अंत तक सभी चिकित्सा महाविद्यालय का होगा उन्नयनः मुख्यमंत्री

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार शाम यहां स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को इस वर्ष के अंत तक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि प्रदेश के लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने हजारों पदों पर भर्ती की है। उन्होंने कहा कि एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं, जिससे मरीजों को बेहतर और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही है।

श्री सुक्खू ने कहा कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर तथा अटल इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पैशियलिटी आयुर्विज्ञान चमियाणा (एआईएमएसएस) में स्थापित की जा रही अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी), शिमला में पीईटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है तथा टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पीईटी स्कैन मशीनों की खरीद की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पैरामेडिकल श्रेणियों के 71 पदों तथा 50 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल श्रेणियों के 162 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा तथा प्रत्येक बैच में 60 विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी, शिमला में तीन लेक्चर थिएटर और एक परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 5.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में लेक्चर थिएटर के निर्माण के लिए अतिरिक्त 14.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपये की आपदा-रोधी आधारभूत संरचना बनेगीः मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और राज्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी (डिजास्टर रेजिलिएंट) आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। वह आज शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में आयोजित 'टूवार्डस रेजिलिएंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन हिमालय' विषय पर उच्च स्तरीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है, इसलिए यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बना रहता है।

उन्होंने वर्ष 2023 की भीषण आपदा को याद करते हुए कहा कि उस समय लगभग 75,000 पर्यटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंस गए थे। सरकार, मंत्रियों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और आवश्यक सेवाओं को तेजी से बहाल किया गया। उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी की भी सराहना की, जिन्होंने स्वयं चंद्रताल झील क्षेत्र में फंसे लगभग 300 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा में करीब 23,000 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए थे और 51 लोगों की जान चली गई थी। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सरकार ने राहत नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा से मिले अनुभवों के कारण सरकार वर्ष 2025 की आपदा का बेहतर तरीके से सामना कर सकी, जिससे स्थिति गंभीर होने के बावजूद नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बढ़ रही बादल फटने की घटनाएं जलवायु परिवर्तन और बड़े बांधों के जलाशयों से बढ़ते वाष्पीकरण से जुड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज यह समस्या हिमाचल में दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में अन्य राज्यों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विकास की नीतियों में आवश्यक बदलाव और साहसिक फैसले लेने होंगे और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम केवल आधारभूत संरचना के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित, मजबूत और समावेशी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरदार पटेल की एकता और संघवाद की सोच देश की शक्तिः राज्यपाल

शिमला। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल केवल भारत के राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था के भी मजबूत समर्थक थे। उन्होंने कहा कि भारत का संघीय ढांचा दुनिया में अनोखा है, जहां अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं संविधान के माध्यम से एक सूत्र में बंधी हुई हैं जो देश की एकता की मजबूत नींव है।

राज्यपाल आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मता और संघवाद की परिकल्पना' तथा 'वंदे मातरम् की यात्रा- एक प्रदर्शनी' के शुभारम्भ समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारत के उप-राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे नहीं आ सके। इस अवसर पर उप-राष्ट्रपति ने वीडियो के माध्यम से अपना संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि ये दोनों कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय चेतना के दो महत्त्वपूर्ण स्तंभों को समर्पित हैं। वंदे मातरम् की यात्रा- एक प्रदर्शनी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में जागृत हुई राष्ट्रभक्ति की भावना को दर्शाती है, जबकि यह संगोष्ठी सरदार पटेल के उस दूरदर्शी नेतृत्व को याद करती है, जिसने देश को एकजुट कर मजबूत भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस अमर गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रसेवा की भावना का संचार किया। यह प्रदर्शनी केवल पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय जागरण की जीवंत गाथा है, जो विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करेगी।

राज्यपाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका योगदान केवल 560 से अधिक रियासतों के विलय तक सीमित नहीं था। बारडोली सत्याग्रह में उनके नेतृत्व, संगठन क्षमता, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि इन्हीं गुणों के कारण उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के केवड़िया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के निर्माण की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह स्मारक सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण में दिए गए अद्वितीय योगदान को समर्पित है और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का सशक्त प्रतीक है। इस अवसर पर राज्यपाल ने 'वंदे मातरम' पर आधारित कॉफी टेबल बुक, 'दर्शन ऑफ राधाकृष्णनः इटरनल एंड टेम्पोरल' संगोष्ठी की कार्यवाही तथा डॉ. एस. राधाकृष्णन पर आधारित बहुभाषी कविता संग्रह का विमोचन भी किया। उन्होंने प्रसिद्ध शोधकर्ता एवं लेखक अखिलेश झा द्वारा तैयार वंदे मातरम् की यात्रा- एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस प्रदर्शनी के सह-संयोजन में रश्मिता झा तथा शोधकर्ता श्रेयसी झा का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इससे पूर्व, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की अध्यक्ष प्रो. शशि प्रभा कुमार ने संस्थान की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने सरदार पटेल की एकता और संघवाद की सोच को आज भी प्रासंगिक बताते हुए भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को सही दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करने की संस्थान की प्रतिबद्धता दोहराई। 'ऑर्गेनाइजर वीकली' के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने सरदार पटेल के अखंड भारत के निर्माण में ऐतिहासिक योगदान पर अपने विचार साझा किए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने राज्यपाल को सम्मानित किया तथा संगोष्ठी और प्रदर्शनी की जानकारी दी।

नदी-नालों के किनारे जाने एवं विभिन्न गतिविधियों पर रोक सम्बन्धी आदेश जारी-

सोलन। ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत नदी-नालों एवं खड्डों इत्यादि के किनारें न जाने बारे आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन ज़िला की सीमा में अश्वनी खड्ड में, खड्ड के दोनों किनारों पर तथा इसके आस-पास के स्थानों और सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अधिकतर मौकों पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि पर्यटकों के जीवन को खतरा पैदा कर सकती है।

पीएमजीएसवाइ सड़कों का निरीक्षण अब एआई से, डिप्टी सीएम शर्मा का बड़ा फैसला

रायपुर, एजेंसी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए राज्य सरकार अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। सड़कों की मॉनिटरिंग और मरम्मत कार्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को महानदी भवन में पीएमजीएसवाई के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस एआई आधारित सड़क निरीक्षण प्रणाली को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

हर महीने वीडियो से होगी सड़कों की जांच-समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि इस नई तकनीक के तहत अब राज्य की प्रत्येक पीएमजीएसवाई सड़क का हर महीने वीडियो आधारित निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए विशेष एआई आधारित ऐप और डैशबोर्ड भी तैयार कर लिया गया है। एआई तकनीक सड़कों पर मौजूद गड्ढों (पॉटहोल्स), दरारों और अन्य क्षतियों की अपने आप पहचान कर उनका विश्लेषण करेगी। इससे सड़कों की रियल टाइम (वास्तविक स्थिति) की सटीक जानकारी मिलेगी और किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचा जा सकेगा।

सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को मिलेगी प्राथमिकता-उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि एआई तकनीक से प्राप्त आंकड़ों (डेटा) के आधार पर राज्य की सबसे ज्यादा खराब और क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान प्राथमिकता से की जाएगी। इसके बाद उनके संधारण (रखरखाव) की बजट कार्ययोजना तैयार कर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे सरकारी संसाधनों का सही और बेहतर उपयोग हो सकेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम व सुरक्षित बनेगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आज से ही प्रायोगिक तौर पर (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक चयनित सड़क का एआई आधारित निरीक्षण शुरू किया जाए। इन शुरुआती निरीक्षणों से मिलने वाले परिणामों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद इसे पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के इस उपयोग से सड़कों की आयु बढ़ेगी और समय पर मरम्मत होने से जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा तथा संचालक एनआरएलएम अश्वनी देवांगन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पत्रकार व समाजसेवी स्व. कुलदीप निगम को श्रद्धांजलि

रायपुर, एजेंसी। पत्रकारिता और समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्व. कुलदीप निगम की 62वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर माना स्थित कुलदीप निगम वृद्धाश्रम एवं मानसिक दिव्यांग बालगृह में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने स्व. निगम की प्रतिमा एवं छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनके सेवा-संकल्प को नमन किया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों तथा मानसिक दिव्यांग बालक-बालिकाओं को फल एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। अपने संबोधन में प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने कहा कि स्व. कुलदीप निगम केवल एक वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं, बल्कि समाज के कमजोर, निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने पत्रकारिता के साथ-साथ समाजसेवा को अपना जीवन-धर्म बनाया। माना कैंप में छत्तीसगढ़ के प्रथम वृद्धाश्रम की स्थापना कर उन्होंने बुजुर्गों की सेवा का जो अभियान शुरू किया, वह पिछले 37 वर्षों से निरंतर मानवता की मिसाल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि स्व. कुलदीप निगम छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संस्थापक सदस्य एवं प्रथम महासचिव रहे। उनके प्रयासों से मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की सेवा और संरक्षण का कार्य संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। साथ ही उन्होंने ऐसे बहादुर बच्चों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों का जीवन बचाकर साहस का परिचय दिया। उनके प्रयासों से अनेक बच्चों को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए। मोहन तिवारी ने कहा कि स्व. निगम द्वारा बोया गया सेवा का बीज आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है और उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। इस अवसर पर कुलदीप निगम वृद्धाश्रम के अध्यक्ष राजेन्द्र निगम, सचिव बिमल घोषाल, प्रीति निगम, पारुल चक्रवर्ती, लीला यादव, सत्यम निगम सहित वृद्धाश्रम एवं बालगृह के कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं स्व. कुलदीप निगम के पैतृक गांव नर्रा स्थित शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं समाजसेवा के कार्यों को स्मरण किया।

एनआईटी रायपुर का कैंपस प्लेसमेंट: 217 कंपनियों ने दिया मौका, 60 लाख का मिला सर्वाधिक पैकेज

रायपुर, एजेंसी। एनआईटी ने वर्ष 2025-26 के कैंपस प्लेसमेंट में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के अनुसार इस वर्ष अब तक 217 कंपनियों ने कैंपस में भाग लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 87 कंपनियां अधिक हैं। इन कंपनियों ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 738 विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। स्नातक स्तर पर एकल आफर के आधार पर 636 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जबकि प्लेसमेंट दर बढ़कर 74 प्रतिशत पहुंच गई है। सर्वाधिक वार्षिक पैकेज 60.3 लाख रुपये तथा औसत पैकेज 12.39 लाख रुपये रहा।

अमेजन, माइक्रोसाफ्ट, ओरेकल व अन्य कई कंपनियां आई-इस साल एनआईटी कैंपस सलेक्शन देश की कई बड़ी कंपनियों ने विद्यार्थियों को अवसर दिया। जिसमें प्रमुख कंपनियों में अमेजन, माइक्रोसाफ्ट, डी.ई. शा, ब्लैकराक, ओरेकल, वीजा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सैमसंग आरएंडडी, श्लम्बरजर, डेलायट, एक्सेंचर, जेडएस एसोसिएट्स, एलएंडटी, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आदित्य बिड़ला समूह सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हुए।

सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल में अच्छी कैंपसिंग-बांच यानी शाखावार की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 98 प्रतिशत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 90 प्रतिशत, केमिकल इंजीनियरिंग में 87 प्रतिशत तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 86 प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन हुआ। वहीं कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिले। आइटी और साफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ ही फिनटेक, कंसल्टिंग, अनुसंधान एवं विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग और शिक्षा क्षेत्र में भी विद्यार्थियों का चयन हुआ।

प्रदेश में अगले 4 दिन कम बारिश होगी

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। फिलहाल प्रदेश में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है, लेकिन अब भी मौसमी बारिश सामान्य से 15 प्रतिशत कम है। 1 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में 242.8 मिमी (9.5 इंच) बारिश दर्ज की गई, जबकि इस दौरान सामान्य तौर पर 284.6 मिमी (11.2 इंच) बारिश होनी चाहिए थी। वहीं तापमान की बात करें तो शुक्रवार को दुर्ग में सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) अभी भी सक्रिय है। इसके साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 9.5 किमी तक फैला हुआ है। हालांकि यह सिस्टम अगले 24 घंटे में कमजोर पड़ सकता है। वहीं मानसून ट्रफ भी उत्तर भारत से होकर गुजर रही है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर बना हुआ है।

साय सरकार का बड़ा कदम: उद्योगों को मिलेगी आसान मंजूरी

छत्तीसगढ़ बनेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी और अनावश्यक जटिलताओं से राहत मिलेगी। विधेयक में डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एक ही गतिविधि के लिए अलग-अलग विभागों से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को खत्म करने का भी प्रस्ताव है। सरकार के अनुसार, आवेदन तय समय सीमा में लंबित रहने पर डीम्ड परमिशन की व्यवस्था लागू होगी, जिससे निवेश प्रस्ताव प्रशासनिक देरी का शिकार नहीं होंगे। वहीं पात्र उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलने से बार-बार निरीक्षण और दस्तावेजी प्रक्रिया कम होगी। प्रस्तावित कानून में जोखिम के आधार पर निरीक्षण व्यवस्था लागू करने का प्रावधान भी रखा गया है। इससे नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को अनावश्यक जांच से राहत मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खासतौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कानून लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ उद्योगों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिहाज से आकर्षक राज्य के रूप में उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने जारी की महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त, 626.25 करोड़ रुपये अंतरित

रायपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना एक मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में होगा राज्य स्तरीय समारोह

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समारोहों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन सुबह 9 बजे से किया जाएगा। समारोह में आकर्षक परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य देशभक्ति से जुड़े आयोजन होंगे। परेड की तैयारियों और रिहर्सल की जिम्मेदारी पुलिस उप महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को दी गई है। वहीं ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस महानिरीक्षक रायपुर संभालेंगे। समारोह स्थल की साफ-सफाई, मंच, पंडाल और बैठक व्यवस्था नगर निगम रायपुर द्वारा की जाएगी। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन स्कूल शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग करेंगे, जबकि रिहर्सल एवं अन्य व्यवस्थाएं कलेक्टर रायपुर के निर्देशन में कराई जाएंगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 7 से 15 अगस्त तक सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करेगा। जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शीघ्र ही विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव, सचिव, कलेक्टर रायपुर तथा गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

चतुर्भुजी मंदिर परिसर की प्राचीन बावड़ी बनी काल, दो मासूमों की डूबने से मौत

रायपुर, एजेंसी। धरसीवां थाना क्षेत्र स्थित कुंबरगढ़ के प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मंदिर परिसर की प्राचीन बावड़ी में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही धरसीवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को बावड़ी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान साक्षी साहू (7 वर्ष) और श्रवण धीवर (4 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों बच्चे धरसीवां विकासखंड के कुर्रा गांव के निवासी थे।

गोताखोर उतरे, पुलिस को सूचित किया-ग्रामीणों ने तत्काल बच्चों की तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों बच्चों को बावड़ी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा गया।

गहरी है प्राचीन बावड़ी-घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे कुर्रा गांव और आसपास के क्षेत्र में मातम का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर की यह प्राचीन बावड़ी काफी गहरी है और इसके आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था या घेराबंदी नहीं होने के कारण हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है।

घेराबंदी करने की उठी मांग-धरसीवां थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

प्रशासन ने मुंह फेरा, ग्रामीणों ने खुद बनाया रास्ता, ईंट-सीमेंट से खड़ा किया पुल

रायपुर, एजेंसी। बलौदाबाजार। बारनवापारा से भोथाही, अमेठी घाट होते हुए जिला मुख्यालय बलौदाबाजार को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित बालमदेही नदी का पुल पिछले छह वर्षों से क्षतिग्रस्त है। पुल टूटने के कारण करीब 25 से 30 गांवों के हजारों ग्रामीणों को हर साल बारिश के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आवेदन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं हो सका। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और जनसहयोग से टूटे हुए पुल के दोनों ओर ईंट और सीमेंट की मजबूत दीवार बनवाई तथा बीच में मुरुम भरकर आवागमन फिर से शुरू कराया। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए मजबूरी में यह व्यवस्था करनी पड़ी।

2019 में ढहा था पुल-जानकारी के अनुसार पाड़दाह और सैहाभाठा के बीच वन क्षेत्र में बालमदेही नदी पर वर्ष 2005-06 में पुल का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2019 की भारी बारिश में पुल का बीच का पिलर ढह गया, जिससे पुल का लेंटर 'वी' आकार में झुल गया और सुरक्षित आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। तब से ग्रामीण हर वर्ष टूटे हिस्से पर मुरुम डालकर अस्थायी रास्ता बनाते हैं, लेकिन बारिश आते ही वह बह जाता है।

हर साल वही समस्या-इस वर्ष 5 और 6 जुलाई को हुई बारिश में भी पुल पर डाला गया मुरुम बह गया। इससे स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। प्रशासन से तत्काल कोई राहत नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने स्वयं पहल की।

ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और जनसहयोग से टूटे हुए पुल के दोनों ओर ईंट और सीमेंट की मजबूत दीवार बनवाई तथा बीच में मुरुम भरकर आवागमन फिर से शुरू कराया। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए मजबूरी में यह व्यवस्था करनी पड़ी।

एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान

सलीमा टेटे समेत 20 खिलाड़ियों को मौका

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों के दौरान भारत की 20 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कमान संभालेंगी। सलीमा की कप्तानी में ही भारत ने पिछले महीने न्यूजीलैंड में एफआईएच नेशंस कप में अपराजेय रहकर खिताब जीतने के साथ प्रो लीग में वापसी की थी।

भारत के मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा ,'हमारे पास ऐसी टीम में जिसमें जूनियर, अनुभवी खिलाड़ियों और सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है जो लगातार एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये प्रयास करते हैं।' पद्मश्री से नवाजी गई सविता और बिछू देवी खारीबम टीम में दो गोलकीपर होंगी। वहीं डिफेंस में सुशीला चाजू, इशिका चौधरी और ज्योति के साथ एफआईएच नेशंस कप के जरिये सीनियर टीम में पदार्पण करने वाली लालथांटलुआंगी और शिल्पी डबास को मौका दिया गया है।

दीपिका ने की थी नेशंस कप में सर्वाधिक गोल- मिडफील्ड का जिम्मा सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिटा टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग पर रहेगी । फॉरवर्ड पंक्ति में लालरेम्सियामी, रूतुजा पिसाल, नवनीत कौर, बलजीत कौर और नेशंस कप में सर्वाधिक छह गोल करने वाली दीपिका हैं। मारिन ने कहा ,'इस समूह ने साबित कर दिया है कि वे फॉर्म में हैं और फिट भी। हमें यकीन है कि यह टीम एशियाई खेलों की चुनौती के लिये तैयार है।'

नेपाल दौरे पर जाएगी इंडिया ए

दिसंबर में खेली जाएगी 3 मैचों की सीरीजः रिपोर्ट

नई दिल्ली। नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी की कवायद में दिसंबर में इंडिया ए की टीम नेपाल का दौरा करने वाली है। 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। ये मैच 9,11 और 13 दिसंबर को खेले जाएंगे।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार तीन मैचों की सीरीज को दोनों पड़ोसी देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को मजबूत करने और दोनों तरफ के उभरते खिलाड़ियों को मौका देने की लगातार कोशिशों के तहत तय किया गया है। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब इस साल की शुरुआत में नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त प्रदर्शन किया है।

3 मैचों की टी20 सीरीज का शेड्यूल

- 9 दिसंबर - पहला
- 11 दिसंबर - दूसरा
- 13 दिसंबर - तीसरा

टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल ने किया प्रभावित- टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल की टीम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई ,लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले मैच में दो बार की चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ उलटफेर करने के करीब थी। इंग्लैंड को केवल 4 रनों से जीत मिली थी। उसने आखिरी लीग मैच में स्कॉटलैंड को हराया। इससे पहले नेपाल एशिया कप में भी खेलता दिखा है।

सर्वेश कुशारे ने रचा इतिहास

डायमंड लीग में वह कर दिखाया जो नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के हाई जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी सर्वेश अनिल कुशारे ने शुक्रवार (10 जुलाई) को मोनाको में डायमंड लीग में तीसरे नंबर पर रहकर इतिहास रचा। वह डायमंड लीग में डेब्यू करते हुए शीर्ष-3 में रहने वाले पहले भारतीय बने। विश्व के दिग्गज खिलाड़ी ओलेह डोरोशचुक, पूर्व ओलंपिक चैंपियन मुताज बारशिम, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट जान स्टेफेला और जैक किमानी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का मुकाबला करते हुए कुशारे 2.26 मीटर कूदकर किमानी और डोरोशचुक से पीछे रहे।

कुशारे से पहले नीरज चोपड़ा, विकास गौड़ा और श्रीशंकर मुरली वह भारतीय हैं,जो डायमंड लीग में टॉप-3 रहे हैं। महाराष्ट्र के 31 साल के कुशारे ने 2.16 मीटर की ऊंचाई से शुरुआत की और 2.26 मीटर तक आसानी से पहुंच गए, लेकिन 2.28 मीटर की ऊंचाई पार करने में उन्हें मुश्किल हुई और डायमंड लीग में डेब्यू करते हुए तीसरे स्थान पर रहे।

कुशारे का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट

पिछले दो सालों में कुशारे के लिए यह दूसरा बड़ा टूर्नामेंट है। इससे पहले वह 2025 टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में छठे स्थान पर रहे थे। दुनिया में 9वें स्थान पर काबिज इस सीजन में सिर्फ तीन जंपर्स ही सर्वेश के 2.31 मीटर के मार्क को बेहतर कर पाए हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में कुशारे ने 2.31 मीटर की छलांग लगाकर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा।

कुशारे के नाम रिकॉर्ड

हाल ही में भुवनेश्वर में इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में कुशारे ने 2.31 मीटर की छलांग लगाकर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। सर्वेश कुशारे ने 2018 में तेजस्विन शंकर के बनाए नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2022 में नेशनल गेम्स में 2.27मीटर की जंप लगाने के तीन साल बाद सर्वेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2.28 मीटर का जंप लगाकर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया।

'वैभव को खिलाना भावनात्मक फैसला

संजू को बाहर करना तर्कहीन',भारतीय टीम पर भड़के पार्थिव पटेल

नई दिल्ली। संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका देने को लेकर भारतीय टी20 टीम पर पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस युवा बल्लेबाज को टीम में जगह देना भावनात्मक रूप से सही फैसला है, लेकिन इसके लिए सीनियर बल्लेबाज को टीम से बाहर करना तर्कहीन है। पार्थिव पटेल ने यह भी स्वीकार किया कि अतीत में संजू सैमसन को प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रखने के कारण टीम

से बाहर कर दिया गया था लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला में उन्हें बाहर करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। पटेल ने जियोस्टार से कहा, 'हमेशा संजू सैमसन को ही क्यों बाहर किया जाता है। अगर आप पिछले 11-12 सालों में संजू सैमसन के करियर को देखें तो एक चीज शुरू से उनका पीछा कर रही है और वह है उनके खेल में निरंतरता का अभाव।'

वैभव सूर्यवंशी को मौका देना भावनात्मक रूप से सही फैसला- पार्थिव ने कहा, 'या तो उस खिलाड़ी को बाहर किया जाता है जो तेजी से रन नहीं बना पा रहा हो या फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हो। आप भावनाओं और तर्क दोनों के आधार पर फैसले नहीं ले सकते। इसलिए वैभव सूर्यवंशी को मौका देना भावनात्मक रूप से सही फैसला था।'

'अब जा रहा है तो नीचे नहीं आना'

भारतीय टीम में प्रभसिमरन सिंह के चयन पर बोले बीमार पिता

नई दिल्ली। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में प्रभसिमरन सिंह का चयन हुआ है। पंजाब के इस खिलाड़ी को जब चयन की जानकारी मिली तब वह जिम में पसीना बहा रहे थे। वह इस पल की काफी समय से उम्मीद कर रहे थे। भारतीय टीम में चयन की खबर मिलने के प्रभसिमरन सिंह सीधे घर पहुंचे। उन्होंने इसकी जानकारी अपने बीमार पिता सरदार सुरजित सिंह को दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रभसिमरन सिंह के पिता गंभीर बीमारों से जूझ रहे हैं। रोज डायलिसिस होती है। ठीक न होने के बाद भी वह अपने बेटे का मैच शायद ही कभी नहीं देखते। प्रभसिमरन ने उन्हें जब यह जानकारी दी तो पिता भावुक हो गए।

अब जा रहा है तो नीचे नहीं जाना

प्रभसिमरन ने कहा, 'पापा की तबीयत ऐसी है कि वो खुद से उठ नहीं पाते, लेकिन जब हमने उन्हें यह खबर दी तो वह खुद उठ गए। अगर यह खुशी एक प्रतिशत भी उनके स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो बस यही बोल रहे थे अब जा रहा है तो नीचे नहीं जाना। और बस एक बात कही और मेहनत करो।'

प्रभसिमरन को संघर्ष के बाद सफलता मिली- आईपीएल के शुरुआती सालों में लगातार मौके मिलने में मुश्किलों का सामना करने के बाद प्रभसिमरन को 2023 में सफलता मिली। उन्होंने 358 रन बनाए, जिसमें उनका पहला आईपीएल शतक भी शामिल था।

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

लॉर्ड्स में अर्धशतक लगाकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 58 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया। वह लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। इतना ही नहीं, महिला क्रिकेट में भी यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दुनिया की पहली खिलाड़ी हैं।

हरमनप्रीत ने लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 121 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल रहे। इससे पहले वह इसी मैदान पर वनडे और टी20 इंटरनेशनल में भी अर्धशतक जड़ चुकी थीं। इसी के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।पुरुष क्रिकेट में कई बल्लेबाजों ने लॉर्ड्स पर टेस्ट और वनडे में अर्धशतक लगाए हैं। युवराज सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में भी यहां पचासा लगाया था, लेकिन उन्हें लॉर्ड्स में कभी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। इसलिए वह तीनों फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने का यह रिकॉर्ड नहीं बना सके।

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा यह मुकाबला लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट है। ऐसे में हरमनप्रीत कौर इस ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में अर्धशतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं।

टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक

स्मृति ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड हासिल की बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की सीरीज लॉर्ड्स, लंदन में खेली जा रही है। इस मैच में इंग्लैंड के टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने को कहा। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने बेहद धैर्य के साथ बैटिंग करते हुए अर्धशतक लगाया और एक छक्का व 11 चौकों की मदद से 83 रन बनाकर आउट हुईं। भारत ने पहली पारी में अपना पहला विकेट तब गंवा दिया जब टीम का स्कोर सिर्फ 4 रन ही था। टीम की ओपनर शैफाली वर्मा बिना खाता खोले यानी डक पर ही आउट हो गई और उसके ठीक बाद भारत का दूसरा विकेट 37 रन के स्कोर पर गिरा जब यास्तिका भाटिया 12 रन पर आउट हो गई। इसके बाद स्मृति ने बेहद धैर्य के साथ बैटिंग करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया।

यही नहीं उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर टीम के लिए 64 रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी की। जेमिमा पहली पारी में 35 रन बनाकर आउट हुईं।

अब फ्रांस से होगा महामुकाबला

फाबियन रूइज और मेरिनो के गोल से स्पेन सेमीफाइनल में

लॉस एंजिलिस, एजेंसी। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। लॉस एंजिलिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फाबियन रूइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए, जबकि बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी केटेलारे ने एकमात्र गोल दागा। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मौजूदा उपविजेता फ्रांस से होगा। यह मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला जाएगा।

फाबियन रूइज ने दिलाई शुरुआती बढ़त

स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने सभी को चौंकाते हुए पेड्री की जगह फाबियन रूइज को शुरुआती एकादश में मौका दिया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। मैच के 30वें मिनट में बेल्जियम के गोलकीपर थिबाउट कूर्तुआ ने दानी ओल्मो का पहला शॉट रोक लिया, लेकिन रीबाउंड पर फाबियन रूइज ने शानदार फिनिश करते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद युवा स्टार लामिन यामाल ने भी बेहतरीन मौका बनाया, लेकिन उनका शॉट मामूली अंतर से गोलपोस्ट के बाहर निकल गया।

मैच में कौन से रिकॉर्ड बने?

बेल्जियम के चार्ल्स डी केटेलारे ने स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन के लगातार 560 मिनट तक गोल नहीं खाने के रिकॉर्ड का अंत किया। इस दौरान सिमोन ने इटली के वाल्टर जेंगा के 1990 विश्व कप में बनाए गए 517 मिनट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। स्पेन ने लगातार 36वां मैच बिना हार के पूरा किया। उसने अर्जेंटीना के 2019-2022 के 36 मैचों के अपराजित रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब उससे आगे केवल इटली का 37 मैचों का अपराजित रिकॉर्ड है।

डी केटेलारे ने बेल्जियम की कराई वापसी

पहले हाफ के अंत से ठीक पहले बेल्जियम ने शानदार जवाब दिया। केविन डी ब्रुने ने शानदार थ्रू पास देकर टिमोथी कास्टान्ये को आगे बढ़ाया। कास्टान्ये के सटीक क्रॉस पर चार्ल्स डी केटेलारे ने 41वें मिनट में हेडर के जरिए गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसी स्कोर के साथ पहला हाफ समाप्त हुआ।

मेरिनो ने 88वें मिनट में दिलाई जीत

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन निर्णायक पल 88वें मिनट में आया। बेल्जियम के अनुभवी गोलकीपर थिबाउट कूर्तुआ 71वें मिनट में चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। उनकी जगह आए सेने लामेन्स ने पाउ क्यूबार्सी के दूर से लगाए गए शॉट को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके। रीबाउंड पर हाल ही में मैदान में उतरे मिकेल मेरिनो ने जोरदार शॉट लगाकर गेंद को जाल में पहुंचा दिया और स्पेन को 2-1 की बढ़त दिला दी। अंतिम सीटी तक बेल्जियम बराबरी नहीं कर सका और स्पेन ने जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया।

घर के मंदिर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रख सकते हैं या नहीं

घर के मंदिर में एक भगवान की दो मूर्ति रखना शुभ या अशुभ? लोग अकसर अपने घर के मंदिर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रखकर उनकी पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे करने से घर-परिवार के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। आइए जानते हैं घर के मंदिर में पूजा से जुड़े जरूरी नियम क्या है। घर के मंदिर में लोग देवी-देवताओं की मूर्ति या फोटो रखने को लेकर अकसर दुविधा में रहते है। ऐसे में कई बार लोग एक ही भगवान की दो मूर्ति भी घर के मंदिर में रख देते है। वास्तु गुरु से जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने बताया कि पूजा स्थल में रखी गई मूर्तियों का विशेष महत्व होता है और इन्हें रखने के कुछ सख्त नियम भी होते हैं। कई लोग एक ही भगवान की अलग-अलग मूर्तियां घर के मंदिर में रख लेते है। इस छोटी सी गलती के कारण घर के माहौल पर बुरा असर पड़ता है। आइए जानते हैं घर के मंदिर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रखने को लेकर क्या नियम हैं।

घर के मंदिर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रखने से ऊर्जा का टकराव हो सकता है। एक ही भगवान की दो मूर्तियां आस-पास रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा आपस में टकराती है। जिससे घर के माहौल पर बुरा असर पड़ता है और परिवार के लोगों के बीच झगड़े बढ़ते हैं।

इसके अलावा घर में दो मूर्तियां होने से धन का नुकसान भी होता है और खर्चे बढ़ते हैं। इसके साथ ही घर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रखने से वास्तु दोष भी लगता है। जो आगे चलकर आर्थिक नुकसान का कारण बनता है।

मंदिर में एक भगवान की दो मूर्ति रखने से परिवार के लोगों के बीच गुस्सा और अहंकार बढ़ता है। इसकी वजह से घर की खुशियां और शांति कम होने लगती हैं।

इसके कारण घर रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी असर होता है। घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा छोटी-मोटी बीमारियों से परेशान रहता है। इसके अलावा घर के लोगों पर धीरे-धीरे कर्ज का बोझ भी बढ़ता है।

नौकरी या व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये नुकसानदायक माना जाता है। इससे व्यापार में चलते हुए काम अचानक रुक जाते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो तरक्की मिलने में बहुत ज्यादा समस्या आती है।

घर के मंदिर में मूर्ति रखने के सही नियम

मंदिर में किसी भी देवी-देवता की केवल एक ही मूर्ति या तस्वीर रखना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा घर के अंदर रखने वाली मूर्ति का आकार हमेशा 3 से 4 इंच छोटा होना चाहिए। अगर कोई मूर्ति टूट जाए या खंडित हो जाए तो उसे घर से हटा कर किसी पेड़ के नीचे या नदी में बहा दें। घर के मंदिर में हमेशा साफ और सीमित मूर्तियों रखने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है।

सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, जानें क्यों सरसों का तेल काले तिल रात के समय दान करना शुभ

शास्त्रों में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान पुण्य का फल तभी मिलता है जब वह सही समय पर किया गया है। शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्यास्त के बाद क्या दान करें और क्या नहीं। दान पुण्य के कार्य करने से मन को सुकून और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी दान पुण्य के बारे में बताया गया है कि दान पुण्य करने से व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन, कई बार गलत तरीके से किए गए दान के कारण व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम गलत समय पर दान कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार, शाम के समय कुछ विशेष चीजों का दान नहीं करना चाहिए। रात के समय किन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए।

किन-किन चीजों का दान करना चाहिए

वैसे तो सूर्यास्त के बाद किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि, दान के लिए शास्त्रों में सूर्योदय के बाद का समय बताया गया है। सूर्योदय के दौरान किए गए दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन, रात के समय सोना, पैसा अन्न आदि का दान करने से बचना चाहिए।

सूर्यास्त के बाद सोने से संबंधित चीज, पैसा और अन्न का

दिन नहीं करना चाहिए। जबकि आप रात के समय शनि से संबंधित चीजें जैसे काले तिल, सरसों तेल, उड़द की दाल और लोहे से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको अपने दान का शुभ फल प्राप्त होगा।

इसके अलावा रात के समय किसी को पैसे उधार देते हैं या दान देते हैं तो आपका शुक्र ग्रह खराब परिणाम दे सकता है। इसके अलावा अन्न जैसे चावल आदि का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि, उनका संबंध भी शुक्र ग्रह से होता है। शाम के समय इन चीजों का दान करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है। इसके अलावा शाम के समय हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब परिणाम दे सकता है। साथ ही शाम के समय नमक का दान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि, नमक का संबंध राहु और चंद्रमा दोनों से बताया गया है। शाम के समय नमक का दान करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, शास्त्रों में शाम का समय मां लक्ष्मी का बताया गया है। यानी इस समय मां लक्ष्मी घर में आगमन करती हैं और घर में समृद्धि लेकर आती हैं। इसलिए जब मां लक्ष्मी आपके घर में आएं तो आप किसी चीज का दान न करें। अगर आपको दान करना है तो सूर्योदय का बाद ही करें।

फ्रिज के ऊपर पानी की बोतल सहित न रखें ये 5 चीजें, घर को घेर लेगी नकारात्मकता

फ्रिज सिर्फ घरेलू उपकरण नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा से जुड़ा भी माना जाता है। ऐसे में इसके ऊपर रखा सामान घर की ऊर्जा को और वहां रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। वास्तु के अनुसार कुछ चीजें फ्रिज के ऊपर रखने से बचना चाहिए। घर में फ्रिज के ऊपर सामान रखने की कई लोगों की आदत होती है। कोई दवाइयों का डिब्बा रख देता है तो कोई पुराने बिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान या रोजमर्रा की दूसरी चीजें। कभी-कभी तो लोग फ्रिज के ऊपर माइक्रोवेव ओवन या एयर फ्रायर भी रख देते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से इसे ठीक नहीं माना जाता है। फ्रिज के ऊपर गलत चीजें रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा अवरुद्ध होती है और आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है।

फ्रिज के ऊपर का स्थान हमेशा साफ और खाली होना चाहिए, क्योंकि ये जगह आपके घर के ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करने का काम करती है। फ्रिज के ऊपर रखी गई हर एक चीज़ आपके जीवन और घर की सुख-शांति पर गहरा असर डालती है। तो चलिए वास्तु गुरु मान्या से जानते हैं कि फ्रिज के ऊपर कौन सी चीज भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए।

फ्रिज के ऊपर न रखें ये चीजे

दवाइयां: फ्रिज के ऊपर दवाइयां रखने से उनका असर कम हो जाता है। वास्तु गुरु मन्या के अनुसार, ऐसा करने से घर के सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं और मेडिकल खर्च बढ़ते हैं।

कचरा और पुराने बिल: वास्तु गुरु मान्या बताती है कि फ्रिज के ऊपर पुराने बिल, फटी-पुरानी डायरी या कोई भी कचरा नहीं रखना चाहिए। इसे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे घर में कलेश बढ़ता है।

पानी या तरल पदार्थ: वास्तु में फ्रिज के ऊपर पानी की बोतल या कोई भी तरल सामान न रखें की सलाह दी जाती है।ऐसे में अग्नि और जल तत्व का टकराव होने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है।

भारी सामान: फ्रिज के ऊपर भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या भारी सामान रखने से घर के मुखिया पर मानसिक दबाव बढ़ता है। जिससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है।

आर्टिफिसियल फूल: फ्रिज के ऊपर आर्टिफिसियल फूल-पौधे रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में रहने वाले लोगों के बीच रिश्ते खराब होते हैं और दूरियां बढ़ती हैं।

क्या कहते आपके सितारे

मेष आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आप अपने बिजनेस में यदि पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल करेंगे, तो वह आने वाले समय में आपको अवश्य समस्या देगी। आप किसी परिजन के घर जा सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा दूर होगी और आप अपने घर के रिनोवेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं, जो विद्यार्थी कहीं बाहर जाकर पढ़ने की सोच रहे थे, तो उन्हें कोई बेहतर अवसर हाथ लगेगा।

वृषभ आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है, लेकिन आप सभी कामों को समय से निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। भाई व बहनों से आपकी खूब पटेगी और रक्त संबंधी रिश्तो में मजबूती आएगी।

मिथुन आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। संतान के करियर को लेकर कोई डिसीजन आप थोड़ा धैर्य रख कर ले और आपकी बेवजह क्रोध करने की आदत के कारण परिवार के सदस्य भी नाराज रहेंगे। आपको अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो कमजोरी महसूस हो सकती है।

कर्क आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। आप अपने बिजनेस में चल रही समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत की आवश्यकता होगी। शेयर मार्केट में आप थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। आपका डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी सामाजिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है।

सिंह आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, लेकिन आपके लंबे समय से रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। आप अपने घर के कामों में भी कोई बदलाव करने की सोचेंगे और रखरखाव पर भी पूरा ध्यान देंगे। आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। सरकारी योजनाओं में धन लगाने से आपको बेहतर लाभ मिलेगा।

कन्या आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप कामों को लेकर योजना तो बनाएंगे, लेकिन आपकी कुछ योजनाओं पर विराम लग सकता है। लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मेहनत जारी रखें। संतान की फरमाइश पर आप उन्हें कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। आप अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके चले, नहीं तो आने वाले समय में आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

तुला आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपके घर परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा आ रही थी, तो वह भी दूर होगी। आप अपने घर मे किसी पूजा-पाठ का आयोजन कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आप किसी दूसरे की मदद के लिए भी आगे आएंगे। आप दानपुण्य के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में आप किसी से बेवजह न उलझे।

वृश्चिक आज का दिन किसी नई संपत्ति की खरीदारी के लिए रहेगा। आपकी सेहत कमजोर रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आप बड़े सदस्यों से राय अवश्य लें, तभी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप जीवनसाथी के लिए कोई नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बनाएंगे।

धनु आज का दिन आपके लिए मौज-मस्ती भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्त आपको इन्वेस्टमेंट संबंधित कोई प्लान बता सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सोच समझकर ही धन लगाए। आपको किसी कानूनी मामले में निराशा हाथ लगेगी। आपकी बिजनेस को लेकर कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है।

मकर आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में अच्छा रहने वाला है। आप इधर-उधर के कामों पर ध्यान थोड़ा कम लगाएंगे। आपको किसी दूसरे के मामले में भी बेवजह बोलने से बचना होगा। आप दिल से काफी खुश रहेंगे, इसलिए आप अच्छा सोचेंगे। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान-सम्मान दिलवाएगी। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि खटपट चल रही थी, तो उसे भी आप दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।

कुंभ आज का दिन आपके लिए मेहनत व ईमानदारी से काम करने के लिए रहेगा। आप गलत तरीके से धन कमाने से बचें और आपको संतान के करियर पर पूरा ध्यान देना होगा, उन्हें एक नई राह दिखानी होगी। जीवनसाथी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है, जिसको लेकर आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपका कोई दूर रह रहा परिजन आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है। आपके बिजनेस में चांद लगेंगे

मीन आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपका कार्यक्षेत्र मे काम को लेकर आइडिया बॉस को खूब पसंद आएगा और वह आपसे काफी खुश रहेंगे। आपके प्रमोशन की बात भी आगे बढ़ सकती है। जीवनसाथी आपके कामों में आपका पूरा साथ देगी। आप अपने परिवार के सदस्यों को साथ मिल-बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपकी धन संबंधित समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करेंगी।

संक्षिप्त समाचार

बांद्रा वेस्ट के हिल रोड पर एक इमारत में लगी आग, दमकल ने काबू पाया

मुंबई, एजेंसी। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में हिल रोड स्थित एक कमर्शियल-कम-रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर शुक्रवार रात 'नेचर्स बास्केट' स्टोर में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया। असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर एसके बांडगर ने कहा कि हमें रात 12:30 बजे 'नेचर्स बास्केट' स्टोर में आग लगने की सूचना मिली, जो खास तौर पर ग्राउंड-फ्लोर के स्टोररूम में लगी थी। उन्होंने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पता चला कि आग बेसमेंट के स्टोररूम में लगी थी। हमने होज लाइन का इस्तेमाल करके आग पर काबू पाया... क्योंकि आग बेसमेंट में थी, इसलिए वहां काफी धुआं जमा हो गया था। हमने अंदर जाने के लिए ब्रीदिंग अपरेटस सेट का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया... किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

10 साल तक सिर्फ कागजों में चलता रहा बीएड कॉलेज, उच्च स्तरीय जांच के आदेश

भोपाल, एजेंसी। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय(बीयू) भोपाल से संबद्ध निजी बीएड कालेजों की मान्यता और संबद्धता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 127 निजी बीएड कालेजों ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन किया था। जांच में 30 कॉलेजों में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। औचक निरीक्षण में विदिशा रोड स्थित श्रीराम कालेज ऑफ एजुकेशन का धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं मिला, जबकि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में कालेज दस वर्षों से संबद्ध है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने अनियमितताओं की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का निर्णय लिया है। शामिल किया जाएगा,जिनमें निरीक्षण बिना कालेजों की प्रोफाइल कार्यपरिषद की मंजूरी से पूर्व ही ई-पोर्टल पर ओके कर अपलोड कर दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह राजपूत ने मार्च में उच्च शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय को शिकायत भेज श्रीराम कालेज की वैधता पर सवाल उठाए थे। एचएल अग्रवाल बीएड कालेज,एचएल अग्रवाल कालेज ऑफ एजुकेशन, इटारसी एक ही पते पर संचालित दर्शाए गए हैं।

कांग्रेस मांग रही बराबरी, मूड में नहीं सपा

अखिलेश ने याद दिलाया 2024 का सबक

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच 'इंडिया' गठबंधन के अंदरूनी समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं। राज्य में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (सपा) से सीटों के बंटवारे में 'बराबरी और सम्मान' की मांग कर सियासत का नया पेंच फंसा दिया है। कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की इस दावेदारी ने गठबंधन में सीट शेयरिंग की उस पुरानी दरार को फिर से उभार दिया है, जो हमेशा से विवाद का विषय रही है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला देकर कांग्रेस को 'बड़ा दिल' दिखाने और क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताने की नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ज्यादा सीटों की अपनी मांग को लेकर आक्रामक है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या सीटों की यह रस्साकशी और बढ़ती बयानबाजी यूपी में विपक्षी एकता के तिलिस्म को चुनाव से पहले ही बिखेर देगी?

गौतम ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन में सीटों की अपेक्षित संख्या से जुड़े सवाल पर कहा, 'हम बराबरी और सम्मान के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 'यथोचित सम्मान' देने से ही जीत का माहौल बनता है। गौतम ने कहा, '2024 के लोकसभा चुनाव में हमने ज्यादा सीट जीतीं। क्षेत्रीय दलों में अब उतनी क्षमता नहीं बची कि वे भाजपा से लड़कर उसे हरा सकें। देश में अकेले राहुल गांधी ही भाजपा से लड़ रहे हैं। '

रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस इन दिनों यूपी में अपना संगठन मजबूत करने पर पूरा फोकस कर रही है, जिसे सीधे तौर पर ज्यादा सीटों की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, सपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी लाना चाहती है। सपा और अन्य सहयोगी दल कांग्रेस के इस 'धीमे रवैये' और ज्यादा सीटों की मांग से चिंतित हैं। गठबंधन के कुछ

धड़ों में यह चिंता सता रही है कि सीटों को लेकर चल रही यह अंदरूनी बहस मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। वर्ष 2024 में सपा और कांग्रेस ने 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के तहत लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। इस दौरान सपा को राज्य की 37 लोकसभा सीट और कांग्रेस को छह सीट पर जीत मिली थी। वहीं, भाजपा 33 सीट ही जीत सकी थी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अगर गठबंधन के तहत कांग्रेस को 'यथोचित सम्मान' नहीं दिया जाएगा, तो इससे भाजपा को 'फायदा' मिलेगा। गौतम ने कहा, 'हम लोकतंत्र को कमजोर करने, लोगों के अधिकारों को कुचलने और दलितों, पिछडों एवं मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाने वाली भाजपा को किसी भी कीमत पर हराने के लिए दृढ़-संकल्पित हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए बराबर का सम्मान जरूरी है।' गौतम ने कहा कि उनकी पार्टी 'पूरे दमखम' से उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीटों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। उन्होंने कांग्रेस से अपील की थी कि वह क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति 'बड़ा दिल' दिखाए। सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश ने कांग्रेस से कहा कि वह क्षेत्रीय पार्टियों को उनके अपने गढ़ में प्राथमिकता दे। उन्होंने कांग्रेस से यह भी कहा कि उसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के फैसलों और उनके अनुमान पर भरोसा करना चाहिए।

मौसम का महाअलर्ट: यूपी समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात का भी खतरा

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कुल 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। भीषण गर्मी से राहत मिलने के साथ ही आसमानी आफत का खतरा भी बढ़ गया है।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में भारी बारिश और आंधी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी भारत में भी बारिश-तूफान का कहर बरप सकता है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली यूपी में अभी एक दो और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तेज झोंकेदार हवाओं के साथ वर्षा का दौर भी जब तब चल सकता है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कुछ इलाकों में बड़े ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है।

अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि

अगले 24 घंटे के दौरान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ओडिशा, कोंकण एवं गोवा, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा के कुछ हिस्सों, उत्तर तमिलनाडु, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण-गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

गंगा की स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है

नमामि गंगे प्रोजेक्ट हुआ सफल, उत्तरकाशी में अब सीधे गंगा में नहीं गिरेगा गंदा पानी

उत्तरकाशी, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने कहा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नमामि गंगे योजना के तहत विकसित सीवरेज नेटवर्क गंगा की स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है।

मिशन के अनुसार, गंगा की शुद्धता उसके उद्गम क्षेत्र से ही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, ताकि नदी का स्वच्छ और अविरल प्रवाह निचले इलाकों तक भी बना रहे। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी आगे चलकर अलकनंदा से संगम के बाद गंगा का स्वरूप ग्रहण करती है।

एनएमसीजी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में नदी को प्रदूषण से बचाना पूरे गंगा बेसिन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि भागीरथी का जल स्रोत से ही स्वच्छ रहेगा, तो इसका लाभ ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों तक पहुंचेगा।

मिशन ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर कहा कि गंगा की सुरक्षा की शुरुआत उसके उद्गम स्थल से ही होनी चाहिए।मिशन के अनुसार, उत्तरकाशी में सीवरेज नेटवर्क का पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण था। प्राकृतिक आपदाओं से बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो चुका था, जबकि पहाड़ी ढलानों, सीमित स्थान और कठोर चट्टानों के कारण निर्माण कार्य भी कठिन था।

इसके बावजूद 2015 में शुरू हुई परियोजना को 2017 में गति दी गई और 2018 में ग्यासू स्थित दो एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन पूरा किया गया। करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से दोनों स्वीकृत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब शहर का अपशिष्ट जल शोधन के बाद ही भागीरथी में छोड़ा जा रहा है। एनएमसीजी का कहना है कि स्रोत पर नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करना पूरी गंगा की पारिस्थितिकी और जल गुणवत्ता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रेम प्रसंग और बीमा की रकम के लिए प्रेमिका के पति को मार डाला

उदयपुर, एजेंसी। प्रेम प्रसंग और बीमा की राशि हासिल करने के लालच में एक युवक द्वारा अपनी प्रेमिका के पति कालू की नृशंस हत्या करने के मामले में बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपित को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का निवासी का गांव की ही शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध था। महिला की बहन को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या से पहले अप्रैल और नवंबर 2024 में कालू के नाम पर करीब 50 लाख रुपये का बीमा कराया गया था, ताकि हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देकर बीमा राशि हासिल की जा सके। 25 दिसंबर 2024 को आरोपितों ने कालू को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। बेहोशी की हालत में हाईवे पर ले जाकर उसके सिर पर डंडे से हमला किया गया और फिर शव को सड़क पर डालकर उस पर तीन बार कार चढ़ाई गई, ताकि पहचान मिटाई जा सके। हालांकि मृतक के हाथ पर अंग्रेजी में गुदे उसके नाम के टैटू से उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान प्रेम संबंध और बीमा पालिसियों के आधार पर मामले का राजफाश किया।

राजस्थान में मौत के आठ दिन बाद एएसआइ का स्थानांतरण

जोधपुर रेंज के आइजी की ओर से जारी 39 एएसआइ की स्थानांतरण सूची में एक ऐसा नाम भी शामिल है, जिसकी एक जुलाई को मौत हो चुकी है। बता दें कि बाड़मेर के बाटाडू चौकी प्रभारी रहे एएसआइ अनोपाराम का निधन जोधपुर के अस्पताल में हुआ था, लेकिन नौ जुलाई को उनका स्थानांतरण बालोतरा कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि अनोपाराम ने पुलिस सेवा की शुरुआत कांस्टेबल के रूप में की थी। बाद में प्रमोशन के बाद वे हेड कांस्टेबल और फिर एएसआइ बने।

दिल्ली-मेरठ रोड की डीपीएसजी रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा अंडरपास

गाजियाबाद , एजेंसी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ रोड स्थित डीपीएसजी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनेगा। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने शुक्रवार को मौके का निरीक्षण कर वहां जाम की स्थिति देखी। इसके बाद अधिकारियों को अंडरपास बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। अंडरपास के बनने से पांच लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। गाजियाबाद को जाम मुक्त करने की दिशा में जीडीए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत शहर के मुख्य जाम पॉइंट डीपीएसजी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने की योजना तैयार की जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग के एक तरफ राजनगर योजना है, जबकि दूसरी तरफ मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में 500 से अधिक इकाइयां संचालित हैं। इन इकाइयों में 50 हजार से अधिक लोग काम करते हैं। साथ ही इस औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा स्कूल और कॉलेज संचालित है। साथ ही यह दिल्ली मेरठ रोड से जुड़ रही है। इस रेलवे क्रॉसिंग का इस्तेमाल राजनगर की तरफ से मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरी करने के लिए जाने वाले कर्मचारी व श्रमिक करते हैं। साथ ही मेरठ रोड के दूसरे तरफ रहने वाली आबादी भी इस रेलवे क्रॉसिंग का इस्तेमाल आरडीसी व्यावसायिक क्षेत्र, कलेक्ट्रेट और कोर्ट में आने जाने का प्रयोग करती हैं। इस कारण ट्रेन आने के दौरान इस रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही यहां अंडरपास बनाने की योजना बनाई जा रही है। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल को निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना यातायात दबाव के कारण लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को अंडरपास निर्माण के लिए सर्वेक्षण, तकनीकी परीक्षण और डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया। रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास का निर्माण होने से मुख्य रूप से राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र, आरडीसी समेत आसपास के लोगों को लाभ होगा। मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में 500 से अधिक इकाइयां संचालित हैं। इनमें काम करने वाले श्रमिक जो डासना, मसूरी आदि क्षेत्रों से आते हैं, वह इसी रेलवे क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, कोर्ट या कलेक्ट्रेट जाने वाले मेरठ रोड स्थित कॉलोनियों के लोग भी इसे रेलवे क्रॉसिंग का प्रयोग करते हैं। ऐसे में यहां अंडरपास लोगों को जाम से राहत देगा।

17 साल के इंफ्लुएंसर ने रचाया निकाह; दुल्हन देख लोग हुए हैरान

इस्लामाबाद एजेंसी। पाकिस्तान के 17 वर्षीय सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर रियल अजान ने निकाह कर अपने प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपने निकाह का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसके बाद यह खबर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि उनकी कम उम्र में शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। निकाह के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने व्हाइट रंग के आउटफिट पहन रखे थे। अजान सफेद कुर्ता-पायजामा और मैचिंग जैकेट में नजर आए, जबकि दुल्हन ने व्हाइट लहंगा और घूंघट के साथ अपना ब्राइडल लुक पूरा किया। दुल्हन ने टीका, हैवी नेकपीस और चूड़ियों के साथ पारंपरिक श्रृंगार किया था। निकाह और मेहंदी समारोह की तस्वीरों में दोनों कैमरे के सामने रोमांटिक अंदाज में पोज देते दिखाई दिए। कई तस्वीरों में दुल्हन घूंघट में नजर आईं। सोशल मीडिया पर दोनों की केमिस्ट्री की खूब तारीफ हो रही है। अजान के फैंस ने उन्हें शादी की शुभकामनाएं दीं और उनकी जोड़ी को क्यूट कपल तथा मेड फॉर ईच अदर बताया। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने 17 साल की उम्र में शादी करने के फैसले की आलोचना की और कहा कि इतनी कम उम्र में शादी का संदेश युवाओं पर गलत असर डाल सकता है।

वियतनाम में फु क्वोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हनोई। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास बड़ा हादसा हो गया है, जहां भारतीय नाविकों से भरी नाव समुद्र में पलट गई है। हनोई में भारतीय दूतावास ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा हादसे की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। डूबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खोज और बचाव अभियान जारी रहने के बीच भारतीय मिशन ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। दूतावास ने कहा कि स्थानीय अधिकारी घटना की पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक दुखद घटना में शनिवार को वियतनाम में फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई है। आपातकालीन स्थिति में पीड़ितों की मदद और जानकारी के लिए हो ची मिन्ह सिटी में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और हनोई स्थित दूतावास में 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। पहले कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है– +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 और +84 33 452 0414।

किराए के लिए खाली है

1- 3600 वर्ग फुट कमर्शियल 4 हॉल सेमी फर्निश्ड सेक्टर 10 टी सी सी काम्प्लेक्स फरीदाबाद में।
2- 1620 वर्ग फुट ऑफिस सेमी फर्निश्ड मेन रोड सेक्टर 10 टी सी सी काम्प्लेक्स फरीदाबाद में।
3- टू बैड रूम सेट ग्राउंड फ्लोर वेल फर्निश्ड सेक्टर 7 डी ब्लॉक फरीदाबाद में।
4- वन रूम सेट वेल फर्निश्ड सेकंड फ्लोर सेक्टर 7 डी ब्लॉक फरीदाबाद में।
इच्छुक व्यक्ति फोन नंबर 9999446252, 9811157562 पर संपर्क करें।

- सूचना -

फरीदाबाद जिला में भेदीनजर समाचार में अपने समाचार, विज्ञापन देने और अखबार की कापी प्राप्त करने के लिये सम्पर्क करें-
1- [illegible]
[illegible]
मोबाइल नम्बर- 9811477204
2- [illegible]
[illegible] एन.आई.टी. नम्बर-5 फरीदाबाद
मोबाइल - 9810229192
3- [illegible] ओल्ड फरीदाबाद
मोबाइल- 9811159238

छोटा विज्ञापन बड़ा फायदा
आज ही स्पेस बुक कराएं-काल करें
0120-4152063,
9811157562

नई एवं तरोताजा खबरों के लिए भेदी नज़र पढ़िए, समय के साथ चलिए
सुनहरा मौका वार्षिक ग्राहक बनिए और
वीआईपी एल्फा सूटकेस कीमत रु, 900 प्राप्त करिए
भेदी नजर समाचार पत्र के ग्राहक बनें
मात्र 700 रूपये दीजिए और वार्षिक ग्राहक बनने के अलावा तुरंत पाइए
और अन्य आकर्षक उपहार के लिए
बम्पर ड्रा
पहला इनाम

एक हीरो बाईक
दूसरा इनाम

एक सोनी एलसीडी 32 इंच व अन्य आकर्षक ईनाम
तीसरा इनाम
बीस मोबाईल फोन
- कोई भी व्यक्ति एजेंट 500 से अधिक मेंबर बना लेगा तो उसे अलग से उपहार दिया जाएगा।
- ये स्कीम एक जनवरी 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक चलेगी।
- 31 दिसम्बर 2026 को 1000 सदस्य बनाने पर बम्पर ड्रा निकाला जाएगा जिसमें उपरोक्त इनाम हरियाणा के किसी भी मंत्री द्वारा दिए जाएंगे।
- ड्रा बम्पर ड्रा में भेदी नजर के वार्षिक मेम्बर ही भाग ले सकते हैं।
- भेदी नजर प्रत्येक माह की पहली तारिख को छपन छापेगा।

आर.एन.आई. नं.
DEL/HIN/2004/13528
प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी एवं संपादक उमा शर्मा द्वारा
उमा पब्लिकेशनस्
1001/1002 दसवां तल नौरंग हाऊस, 21 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -1 से प्रकाशित
एवं नीलू प्रिंटिंग प्रेस
ई-33 सेक्टर -7 नोएडा से मुद्रित
संपादक
उमा शर्मा
प्रधान संपादक
गिरीश चन्द्र शर्मा
फोन नं. -
011-66304689
0120-4189808
0129-2290152
0129-2267 07 8
0129-2977562
फैक्स नं. -
011-66304690
0129-2297 640
मो. : 9811157 562,
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र फरीदाबाद होगा ।
पीआईबी एक्ट अनुसार सभी विवादित समाचारों की ज़िम्मेदारी समाचार लेखक की होगी भेदीनज़र संस्थान ,संपादक और प्रधान संपादक क़ानूनन ज़िम्मेदार नहीं होगा